सारांश
मानव विकास रिपोर्ट 2011
संवहनीयता और समता:
सबके लिए एक बेहतर भविष्य

वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक सेहतमंद और ख़ुशहाल ज़िन्दगी का हक़ सुरिक्षत कर पाना 21वीं सदी में विकास की एक बड़ी चुनौती है। वर्ष 2011 की मानव विकास रिपोर्ट इस चुनौती के सन्दर्भ में होने वाले वैश्विक विमर्श के लिए कुछ नये और महत्वपूर्ण विचार-बिन्दु प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट यह दर्शाती है कि समता के मूलभूत प्रश्नों से संवहनीयता का कितना जटिल रिश्ता है—ये सवाल हैं निष्पक्षता और सामाजिक न्याय के, एक बेहतर गुणवत्ता वाले जीवन की सुलभता के।

पूर्वानुमान संकेत करते हैं कि गंभीर पर्यावरणीय ख़तरों को और गहराती सामाजिक असमानताओं को घटाने में लगातार मिल रही असफलता ने दशकों की मशक्कत से हासिल की गयी उस प्रगति को धीमा करने का ख़तरा खड़ा किया है जो दुनिया की बहुसंख्य ग़रीब आबादी ने हासिल की है—और मानव विकास के लिए जो वैश्विक सहमति उभरी है, उसकी दिशा उलट जाने का ख़तरा हो गया है। यह रिपोर्ट लोगों, स्थानीय समुदायों, देशों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए उन रास्तों की पहचान करती है जो पर्यावरणीय संवहनीयता और समता को इस तरह से प्रोत्साहित करते हैं कि दोनों एक-दूसरे को पुष्ट कर सकें।

नया विश्लेषण यह दर्शाता है कि राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता समीकरणों में असंतुलन और लैंगिक असमानताएँ किस तरह से साफ़ पानी और बेहतर साफ़-सफ़ाई की घटती उपलब्धता, भू-क्षरण और घरेलू तथा घर के बाहर होने वाले वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों से सीधे जुड़े हुए हैं। यह ये भी स्पष्ट करता है कि किस तरह यह दोनों कारक आय सम्बन्धी असमानताओं से जुड़े हुए दुष्प्रभावों को और गहराते हैं। लैंगिक असमानताएँ भी पर्यावरणीय परिणामों को प्रभावित कर इन्हें बद्तर बना देती हैं। वैश्विक स्तर पर देखें तो अधिशासन (governance) सम्बन्धी व्यवस्थाएँ अक्सर छोटे विकासशील देशों की आवाज़ को कमज़ोर करती हैं और हाशिये पर खड़े समुदाय और अधिक उपेक्षित हो जाते हैं।

इसके बावजूद अ-संवहनीयता और असमानता के विकल्प मौजूद हैं। समता बढ़ाने वाले निवेश—जैसे कि अक्षय ऊर्जा, पानी, साफ़-सफ़ाई और प्रजनन सम्बन्धी स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता बढ़ाने वाले—संवहनीयता और मानव विकास, दोनों को ही पुष्ट करने वाले हो सकते हैं। सशक्त जवाबदेही और लोकतांत्रिक प्रक्रियाएँ भी परिणामों को बेहतर कर सकती हैं। सफल पद्धतियाँ निर्भर करती हैं सामुदायिक प्रबंधन और उन समावेशी संस्थाओं पर जो सुविधाविहीन समुदायों पर विशेष ध्यान देती हैं। सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के आगे, विश्व को ज़रूरत है 2015 के बाद के विकास की रूपरेखा की जो संवहनीयता और समता को प्रतिबिंबित करे। यह रिपोर्ट दर्शाती है कि वे पद्धतियाँ जो समता को नीतियों और योजनाओं में समन्वित करती हैं, और जो राजनैतिक और क़ानूनी क्षेत्रों में बदलाव लाने के लिए लोगों को सक्षम बनाती हैं, उनमें अपार संभावनाएँ हैं।

विकास के लिए वित्तपोषण की ज़रूरत विकास-सहायता के मौजूदा आधिकारिक स्तर से कई गुना ज़्यादा है। उदाहरण के लिए, आज के समय में निम्न-कार्बन ऊर्जा स्रोत पर होने वाला ख़र्च आवश्यकताओं के न्यूनतम आकलन के 2 प्रतिशत से भी कम है। वित्तीयन के प्रवाह को अ-संवहनीयता और असमता से जुडी गंभीर चुनौतियों की तरफ़ केन्द्रित करने की ज़रूरत है। यद्यपि बाज़ार की कार्यविधियाँ और निजी वित्तपोषण तो हमेशा महत्वपूर्ण रहेंगे, लेकिन इसे सक्रिय सार्वजनिक निवेश से उत्प्रेरण भी मिलना चाहिए। वित्तीयन के इस अंतर को भरने के लिए नवाचारी (innovative) सोच की ज़रूरत है, जो यह रिपोर्ट प्रदान करती है।

यह रिपोर्ट समता बढ़ाने और आमजन की आवाज़ मुखर करने में सहायक सुधारों की पक्षधर है। दुनिया भर में आज और आने वाले कल में न्यूनतम सुविधाओं के साथ जीने वाले बंधुओं के प्रति हमारी सामूहिक ज़िम्मेदारी है—यह सुनिश्चित करने की कि वर्तमान भविष्य का दुश्मन नहीं है। यह रिपोर्ट हमारी प्रगति का पथ आलोकित करने में सहायक हो सकती है।

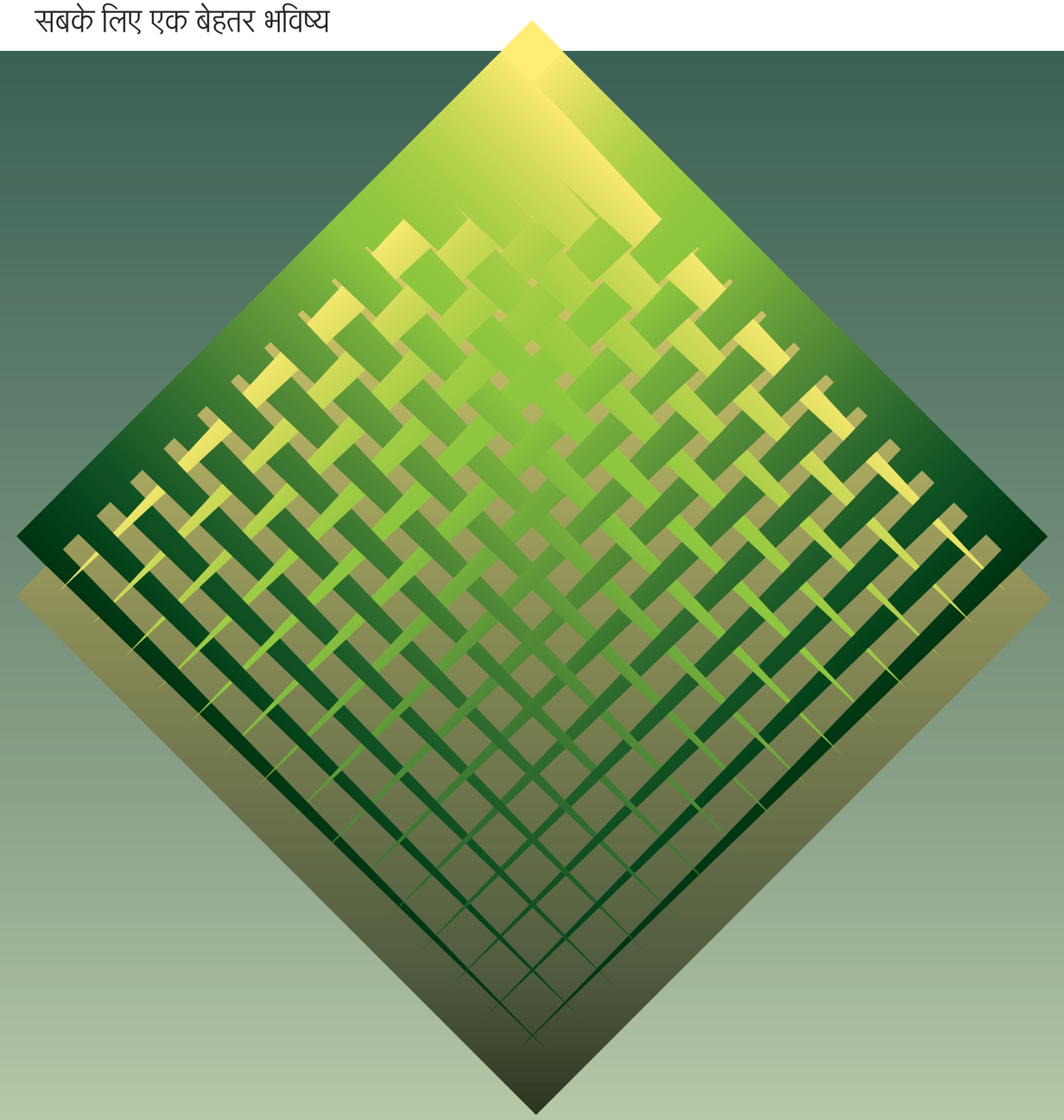

कॉपीराइट © 2011
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अधीन
1 यू.एन. प्लाज़ा, न्यूयॉर्क, एन.वाई. 10017, यू.एस.ए.

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन का कोई भी अंश बिना पूर्वानुमति के न तो पुनर्प्रकाशित किया जा सकता है, न रिट्रीवल सिस्टम में संग्रहीत किया जा सकता है और न ही किसी भी रूप में या किसी तरीके से, इलेक्ट्रॉनिक, मेकैनिकल, फ़ोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग अथवा किसी भी अन्य विधि से प्रसारित किया जा सकता है।

अनुवादः मानव विकास रिपोर्ट के इस सारांश का हिन्दी अनुवाद सम्यक् न्यास द्वारा।

मुद्रकः न्यू कॉन्सेप्ट इन्फ़र्मेशन सिस्टम्स

सम्पादन एवं प्रोडक्शनः कम्युनिकेशन्स डेवलपमेंट इनकॉर्पोरेटेड, वॉशिंगटन डी.सी.
डिज़ाइनः जैरी क्विन

प्रकाशन में रह गयी भूल या छूट के सुधार के लिए कृपया हमारी वेबसाइट http://hdr.undp.org देखें।

मानव विकास रिपोर्ट 2011 की टीम

यू.एन.डी.पी. मानव विकास रिपोर्ट ऑफ़िस

ये मानव विकास रिपोर्ट निदेशक के मार्गदर्शन में शोध, सांख्यिकी, कम्युनिकेशन्स एवं प्रकाशन से जुड़े स्टाफ़ तथा राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्टों की सहायक टीम के संयुक्त प्रयासों का प्रतिफल है। ऑपरेशन्स एवं प्रशासन से जुड़े सहकर्मी कार्यालयीन काम में मददगार रहे हैं।

निदेशक एवं प्रमुख लेखक
जेनी क्लुगमैन

शोध
फ़्रांसिस्को रोड्रीगेज़ (प्रमुख), शीतल बीजाधर, शुभ्रा भट्टाचार्जी, मोनालिसा चटर्जी, ह्यूंग-जिन चोई, एलन फ़्यूस, ममाई गेब्रेसादिक, ज़ाकरी गिडवित्ज़, मार्टिन फ़िलिप हैगर, वीरा केहायोवा, होज़े पिनेडा, ऐमा समन एवं सारा ट्विग।

सांख्यिकी
मिलोराड कोवासेविच (प्रमुख), एस्ट्रा बॉनिनी, एमी गाये, क्लारा गार्सिया अगून्या एवं श्रेयसी झा

कम्युनिकेशन एवं प्रकाशन
विलियम ऑर्म (प्रमुख), बोटागोज़ अब्ड्रेयेवा, कार्लोटा आइएलो, विन्न बोएल्ट एवं ज्याँ-ईव्ज़ हमेल

राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्टें
ईवा जेस्पर्सन (उप निदेशक), मैरी एन मवांगी, पाओला पग्लियानी एवं टिम स्कॉट

ऑपरेशन्स एवं प्रशासन
सरान्तूया मेन्ड (ऑपरेशन्स प्रबंधक), डाऐन बोउप्दा एवं फ़े हुआरेज़-शानाहन

वैश्विक, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्टें

मानव विकास रिपोर्टें: विकास के मुद्दों, रुझानों, प्रगति और नीतियों के आनुभाविक (empirical) पुष्टियों से परिपूर्ण और बौद्धिक रूप से स्वतंत्र विश्लेषणों के रूप में सन् 1990 से यू.एन.डी.पी. द्वारा हर साल वैश्विक मानव विकास रिपोर्टों (एच.डी.आर.) का प्रकाशन हो रहा है। वर्ष 2011 की एच.डी.आर. तथा इसकी पूर्ववर्ती रिपोर्टों से जुड़े सन्दर्भ-स्रोत hdr.undp.org पर निःशुल्क उपलब्ध हैं, इसमें प्रमुख यू.एन. भाषाओं में रिपोर्ट का सम्पूर्ण पाठ एवं सारांश, विमर्शों तथा नेटवर्क परिचर्चाओं के सारांश, मानव विकास शोधपत्र श्रृंखला और एच.डी.आर. समाचार बुलेटिनों समेत आम जानकारी शामिल है। साथ ही, सांख्यिकीय संकेतक, अन्य आँकड़ों के विश्लेषण-सूत्र, इंटरैक्टिव नक्शे, देशों से जुड़े तथ्य तथा एच.डी.आर. से जुड़ी अतिरिक्त जानकारियाँ भी उपलब्ध हैं।

क्षेत्रीय मानव विकास रिपोर्टें: पिछले दो दशकों में यू.एन.डी.पी. के क्षेत्रीय ब्यूरो ऑफ़िसों के सहयोग से 40 से भी अधिक, संपादकीय स्वायत्तता और क्षेत्रीय फ़ोकस वाली क्षेत्रीय मानव विकास रिपोर्टें प्रकाशित हुई हैं। बहुधा उत्तेजक विश्लेषणों, नीतिगत पैराकोरी से सम्पन्न इन रिपोर्टों ने बेहद अहम मुद्दों की पड़ताल की है। जैसे—अरब देशों में नागरिक आज़ादी और महिलाओं का सशक्तीकरण, एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र में भ्रष्टाचार, मध्य यूरोप में 'रोमा' एवं अन्य अल्पसंख्यकों के साथ बर्ताव, लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियाई क्षेत्र में सम्पत्ति का असमता-परक वितरण सरीखे मुद्दे।

राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्टें: सन् 1992 में पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद से यू.एन.डी.पी. के सहयोग और स्थानीय संपादकीय टीमों के प्रयासों से 140 देशों में राष्ट्रीय एच.डी.आर. प्रकाशित हो रही हैं। इन रिपोर्टों ने—अब तक 650 से भी ज़्यादा प्रकाशित हो चुकी हैं—स्थानीय स्तर पर आयोजित परिसंवादों एवं शोध के द्वारा राष्ट्रीय नीतियों के सरोकारों में मानव विकास के दृष्टिकोण को पिरोने का काम किया है। बहुधा ही, इन राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्टों का फ़ोकस लैंगिकता, जातीयता (ethnicity) अथवा गाँव-शहर के बँटवारे पर होता है ताकि असमानता पहचानने में मदद हो सके, प्रगति को मापा जा सके और संभावित संघर्षों के शुरुआती संकेतों को समय रहते खोज लिया जाय। चूँकि इन रिपोर्टों की जड़ें राष्ट्रीय आवश्यकताओं और दृष्टिकोणों में होती है, इनमें से अनेकों का सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों को हासिल करने की रणनीतियों तथा अन्य मानव विकास सम्बन्धी प्राथमिकताओं के निर्धारण के साथ-साथ राष्ट्रीय नीतियों पर उल्लेखनीय प्रभाव रहा है।
राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मानव विकास रिपोर्टों पर अधिक जानकारी तथा सम्बद्ध प्रशिक्षण एवं सन्दर्भ-स्रोतों के लिए कृपया देखें
hdr.undp.org/en/nhdr/।

मानव विकास रिपोर्टें 1990-2010

1990	मानव विकास की अवधारणा एवं मापन
1991	मानव विकास का वित्तीयन
1992	मानव विकास के वैश्विक आयाम
1993	जन भागीदारी
1994	मानव सुरक्षा के नये आयाम
1995	लैंगिकता एवं मानव विकास
1996	आर्थिक प्रगति एवं मानव विकास
1997	निर्धनता निर्मूलन के लिए मानव विकास
1998	मानव विकास के लिए उपभोग
1999	मानवीयतापूर्ण वैश्वीकरण
2000	मानवाधिकार एवं मानव विकास
2001	नयी प्रौद्योगिकियों को मानव विकास में सहायक बनाना
2002	विभाजित विश्व में लोकतंत्र को गहराना
2003	सहस्राब्दि विकास लक्ष्यः ग़रीबी मिटाने के लिए राष्ट्रों के बीच एक समझौता
2004	आज के वैविध्यपूर्ण विश्व में सांस्कृतिक आज़ादी
2005	अंतरराष्ट्रीय सहयोग की दुविधाएँः एक असमान विश्व में सहायता, व्यापार एवं सुरक्षा
2006	अभावों के पारः ऊर्जा, ग़रीबी और वैश्विक जल संकट
2007/2008	जलवायु परिवर्तन से मुक़ाबलाः एक विभाजित विश्व में मानव-एकजुटता
2009	बाधाओं पर विजयः मानव गतिशीलता एवं विकास
2010	देशों की वास्तविक संपदाः मानव विकास के पथ

अधिक जानकारी के लिए नीचे लिखी वेबसाइट देखें:
http://hdr.undp.org

सारांश

मानव विकास रिपोर्ट 2011

संवहनीयता और समताः

सबके लिए एक बेहतर भविष्य

संयुक्त राष्ट्र
विकास कार्यक्रम
(यू.एन.डी.पी.)
के लिए
प्रकाशित

प्रस्तावना

जून 2012 में विश्व के बड़े नेता रियो डी जनेरियो में सर्वसम्मति से कुछ ऐसे ठोस वैश्विक क़दमों पर आम राय बनाने के लिए जुटेंगे, जिनसे धरती के भविष्य और सारी दुनिया में आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सेहतमंद और ख़ुशहाल ज़िन्दगी का हक़ सुरिक्षत हो सके। यह 21वीं सदी में विकास की एक बड़ी चुनौती है।

वर्ष 2011 की मानव विकास रिपोर्ट इस चुनौती के संदर्भ में होने वाले वैश्विक विमर्श के लिए कुछ नये और महत्वपूर्ण विचार-बिन्दु प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट यह दर्शाती है कि समता के मूलभूत प्रश्नों से संवहनीयता का कितना जटिल रिश्ता है—ये सवाल हैं निष्पक्षता और सामाजिक न्याय के, एक बेहतर गुणवत्ता वाले जीवन की सुलभता के। संवहनीयता एकांतिक रूप से (exclusively) या फिर, प्राथमिक रूप से भी एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, और रिपोर्ट में भी इसे ज़ोरदार ढंग से कहा गया है। इसका मूलभूत आशय इससे है कि हम अपनी ज़िन्दगी कैसे जीना चाहते हैं— इस जागरूकता के साथ कि आज हम जो भी करते हैं उसका अंजाम भुगतेंगे 7 अरब लोग, जो आज दुनिया में हैं, तथा वे अरबों-अरब भी, जो आने वाली सदियों में धरती पर क़दम रखेंगे।

पर्यावरणीय संवहनीयता और समता के बीच के सम्बन्ध को समझना बहुत ज़रूरी है, विशेषतया अगर हमें अपनी मौजूदा और आने वाली पीढ़ियों की स्वाधीनताओं का विस्तार करना है। पिछले कुछ दशकों में मानव विकास में जो उल्लेखनीय प्रगति हुई है, और जिसको वैश्विक मानव विकास रिपोर्टों ने बख़ूबी दर्ज भी किया है, वह क़ायम नहीं रह सकती अगर वैश्विक स्तर पर पर्यावरण से जुड़े ख़तरों और असमानता को कम करने के लिए साहसिक क़दम नहीं उठाये गये। यह रिपोर्ट लोगों, स्थानीय समुदायों, देशों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए उन रास्तों की पहचान करती है जो पर्यावरणीय संवहनीयता और समता को इस तरह से प्रोत्साहित करते हैं कि दोनों एक-दूसरे को पुष्ट कर सकें।

जिन 176 देशों और क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम दिन-प्रतिदिन काम कर रहा है, वहाँ के तमाम सुविधाविहीन लोग वंचितता का दोहरा बोझ उठाते हैं। पर्यावरण क्षरण के व्यापक प्रभावों से वे ज़्यादा अरक्षित (vulnerable) होते हैं, क्योंकि उन पर भारी दबाव होते हैं जिनसे पार पाने की सामर्थ्य उनमें कमतर होती है। उनको अपने आसपास के पर्यावरण से, घर के भीतर के वायु प्रदूषण, गंदे पानी और घर की लचर साफ़-सफ़ाई के दुष्प्रभावों के ख़तरों से जूझना ही होता है। पूर्वानुमान संकेत करते हैं कि गंभीर पर्यावरणीय ख़तरों को, और गहराती सामाजिक असमानताओं को घटाने में लगातार मिल रही असफलता ने दशकों की मशक्कत से हासिल की गयी उस प्रगति को धीमा करने का ख़तरा खड़ा किया है जो दुनिया की बहुसंख्य ग़रीब आबादी ने हासिल की है—और मानव विकास के लिए जो वैश्विक सहमति उभरी है, उसकी दिशा उलट जाने का ख़तरा हो गया है।

सत्ता समीकरणों की प्रमुख विषमताएँ इन प्रतिमानों को रूप देती हैं। नया विश्लेषण यह दर्शाता है कि राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता समीकरणों में असंतुलन और लैंगिक असमानताएँ किस तरह से साफ़ पानी और बेहतर साफ़-सफाई की घटती उपलब्धता, भू-क्षरण और घरेलू तथा घर के बाहर होने वाले वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों से सीधे जुड़े हुए हैं। यह ये भी स्पष्ट करता है कि किस तरह यह दोनों कारक आय सम्बन्धी असमानताओं से जुड़े हुए दुष्प्रभावों को और गहराते हैं। लैंगिक असमानताएँ भी पर्यावरणीय परिणामों को प्रभावित कर इन्हें बद्तर बना देती हैं। वैश्विक स्तर पर देखें तो अधिशासन (governance) सम्बन्धी व्यवस्थाएँ अक्सर छोटे विकासशील देशों की आवाज़ को कमज़ोर करती हैं और हाशिये पर खड़े समुदाय और अधिक उपेक्षित हो जाते हैं।

इसके बावजूद अ-संवहनीयता और असमानता के विकल्प मौजूद हैं। मानव विकास के व्यापक सन्दर्भों में देखें तो जीवाश्म ईंधन(fossil fuel) पर आधारित प्रगति एक बेहतर ज़िन्दगी की अनिवार्य शर्त नहीं है। समता बढ़ाने वाले निवेश—जैसे कि अक्षय ऊर्जा, पानी, साफ़-सफाई और प्रजनन सम्बन्धी स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता बढ़ाने वाले—वे संवहनीयता और मानव विकास, दोनों को ही पुष्ट करने वाले हो सकते हैं। सशक्त जवाबदेही और लोकतांत्रिक प्रक्रियाएँ भी, एक सक्रिय नागर समाज और सक्रिय मीडिया को सहयोग देते हुए, परिणामों को कुछ हद तक बेहतर कर सकती हैं। सफल पद्धतियाँ निर्भर करती हैं सामुदायिक प्रबंधन और उन समावेशी संस्थाओं पर जो सुविधाविहीन समुदायों पर विशेष ध्यान देती हैं। ये कुछ ऐसी पद्धतियाँ हैं जो विभिन्न सरकारी एजेंसियों और विकास के साझेदारों के बीच बजटों तथा प्रक्रियाओं का संयोजन करती हैं।

सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के आगे, विश्व को ज़रूरत है 2015 के बाद के विकास की रूपरेखा की जो संवहनीयता और समता को प्रतिबिंबित करे; ऐसे में रियो+20 आगे बढ़ने की एक साझा समझ तक पहुँचने के प्रमुख अवसर की तरह उभरता है। यह रिपोर्ट दर्शाती है कि वे पद्धतियाँ जो समता को नीतियों और योजनाओं में समन्वित करती हैं, और जो

राजनैतिक और क़ानूनी क्षेत्रों में बदलाव लाने के लिए लोगों को सक्षम बनाती हैं, उनमें अपार संभावनाएँ हैं। विभिन्न देशों से मिल रहे अनुभव यह दर्शाते हैं कि इन पद्धतियों में सकारात्मक संगतियाँ (synergies) उपजाने और उनका लाभ लेने की पर्याप्त संभावनाएँ हैं।

विकास—जिसमें पर्यावरणीय और सामाजिक संरक्षण शामिल हैं—के लिए वांछित वित्तपोषण को विकास-सहायता के मौजूदा आधिकारिक स्तर से कई गुना ज़्यादा होना चाहिए। उदाहरण के लिए, आज के समय में निम्न-कार्बन ऊर्जा स्रोत पर होने वाला ख़र्च आवश्यकताओं के न्यूनतम आकलन का भी सिर्फ़ 1.6% है, जबकि जलवायु परिवर्तन से अनुकूलन और उसके दुष्प्रभाव घटाने पर होने वाला व्यय ख़र्च की आकलित ज़रूरतों का 11% है। उम्मीद टिकी है नये जलवायु-वित्तीयन पर। बाज़ार की कार्यविधियाँ और निजी वित्तपोषण तो हमेशा महत्वपूर्ण रहेंगे, लेकिन इसे सक्रिय सार्वजनिक निवेश से उत्प्रेरण भी मिलना चाहिए। वित्तीयन के इस अंतर को भरने के लिए नवाचारी (innovative) सोच की ज़रूरत है, जो यह रिपोर्ट प्रदान करती है।

गहराते पर्यावरणीय ख़तरों से समतापरक ढंग से निबटने के लिए धन के नये स्रोत जुटाने की वक़ालत करने के अलावा यह रिपोर्ट समता बढ़ाने और आमजन की आवाज़ मुखर करने में सहायक सुधारों की पक्षधर है। वित्तीयन के प्रवाह को अ-संवहनीयता और असमता से जुडी गंभीर चुनौतियों की तरफ़ केन्द्रित करने की ज़रूरत है, न कि मौजूदा विषमताओं को बढ़ाने की।

मानव विकास का केन्द्रीय लक्ष्य है हर किसी को सुअवसर और विकल्प मुहैया कराना। आज और आने वाले कल में न्यूनतम सुविधाओं के साथ जीने वाले बंधुओं के प्रति हमारी सामूहिक ज़िम्मेदारी है—और एक नैतिक अनिवार्यता है यह आश्वस्त करने की कि वर्तमान भविष्य का दुश्मन नहीं है। यह रिपोर्ट हमारी प्रगति का पथ आलोकित कर सकती है।

हेलेन क्लार्क
प्रशासक
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम

इस रिपोर्ट में प्रस्तुत विश्लेषण और नीतिगत प्रस्ताव अनिवार्यतया संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अथवा इसकी कार्यकारी परिषद् के विचारों को परिलक्षित नहीं करते। यह रिपोर्ट यू.एन.डी.पी. द्वारा प्रायोजित एक स्वतंत्र प्रकाशन है। इस रिपोर्ट के लिए किया गया शोध एवं इसका लेखन मानव विकास रिपोर्ट टीम और जेनी क्लुगमैन, निदेशक, मानव विकास रिपोर्ट ऑफ़िस के नेतृत्व में श्रेष्ठ सलाहकारों के एक समूह का साझा प्रयास रहा है।

अनुक्रम

प्रस्तावना

आभार

विहगावलोकन

अध्याय 1
संवहनीयता और समता क्यों ?

क्या मानव विकास की सीमाएँ हैं ?

संवहनीयता, समता एवं मानव विकास

हमारी पड़ताल का फ़ोकस

अध्याय 2
मानव विकास, समता और पर्यावरणीय संकेतकों के प्रतिमान एवं प्रवृत्तियाँ

प्रगति एवं संभावनाएँ

टिकाऊ प्रगति के मार्ग में ख़तरे

संवहनीय और समतापरक विकास में मिली सफलता

अध्याय 3
प्रभावों की पड़ताल—सम्बन्धों को समझना

ग़रीबी के चश्मे से देखना

लोगों की खुशहाली के मार्ग में पर्यावरणीय जोख़िम

चरम आपदाओं के असमानता बढ़ाने वाले प्रभाव

निर्बलीकरण और पर्यावरणीय क्षरण

अध्याय 4
सकारात्मक संगतियाँ— पर्यावरण, समता एवं मानव विकास की कारगर रणनीतियाँ

पर्यावरणीय वंचनाओं से निबटने के लिए विस्तारण

और लचीलेपन को मज़बूती

क्षरण की रोकथाम

जलवायु परिवर्तन से निबटना—जोख़िम और वास्तविकताएँ

अध्याय 5
नीतिगत चुनौतिओं का मुक़ाबला

कामचलाऊ रवैया: न समतापरक, न ही संवहनीय

अपने विकास मॉडल पर पुनर्विचार— बदलाव के उत्प्रेरक

निवेश और सुधार के एजेंडे का वित्तीयन

वैश्विक स्तर पर नवाचार

नोट्स

संदर्भ

सांख्यिकीय संलग्नक

पाठकों के लिए मार्गदर्शिका

एच.डी.आई. देश व उनकी श्रेणी, 2011

सांख्यिकीय तालिकाएँ

1 मानव विकास सूचकांक और उसके घटक

2 मानव विकास सूचकांक के रुझान, 1980-2011

3 असमानता-समायोजित मानव विकास सूचकांक

4 लैंगिक असमानता सूचकांक और सम्बद्ध संकेतक

5 बहुआयामी निर्धनता सूचकांक

6 पर्यावरणीय संवहनीयता

7 पर्यावरणीय ख़तरों के मानव विकास पर प्रभाव

8 खुशहाली एवं पर्यावरण के बारे में समझ

9 शिक्षा एवं स्वास्थ्य

10 जनसंख्या एवं अर्थव्यवस्था

तकनीकी नोट

क्षेत्र

सांख्यिकीय संदर्भ

विहगावलोकन

इस वर्ष की रिपोर्ट संवहनीय (sustainable) तथा न्यायसंगत विकास की चुनौतियों पर केंद्रित है। इन दोनों दृष्टिकोणों को मिलाकर देखने पर पता चलता है कि कैसे पर्यावरण का क्षरण पहले से ही वंचित लोगों को प्रतिकूल तरीके से प्रभावित कर असमानता को और गहराता है, तथा कैसे मानव विकास में असमानताएँ पर्यावरणीय क्षरण को और अधिक बढ़ाती हैं।

मानव विकास, जो कि लोगों के लिए विकल्पों के विस्तार से सम्बद्ध है, साझा प्राकृतिक संसाधनों को मानकर चलता है। मानव विकास को बढ़ाने के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय और भूमंडलीय स्तर पर संवहनीयता पर जोर देना ज़रूरी है, और यह केवल उन्हीं तरीकों से किया जाना चाहिए जो सशक्तीकरण करने वाले तथा न्यायसंगत हों।

हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि बेहतर पर्यावरणीय संवहनीयता की ओर बढते हुए ग़रीब लोगों की बेहतर जीवन की आकांक्षाएँ पूरी तरह से ध्यान में रखी जाएँ। और हम ऐसे रास्तों को इंगित करते हैं जो लोगों, समुदायों, देशों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को संवहनीयता तथा समता को इस प्रकार प्रोत्साहित करने में समर्थ करें कि दोनों एक-दूसरे को मज़बूती दे सकें।

संवहनीयता और समता क्यों ?

अपनी दुनिया की एक समझ बनाने के लिए, वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने लिए मानव विकास के इस दृष्टिकोण की एक स्थायी प्रासंगिकता है। पिछले वर्ष मानव विकास रिपोर्ट (एच.डी.आर.) ने अपने बीसवें संस्करण में इस बात पर ज़ोर दिया कि कैसे समता, सशक्तीकरण और संवहनीयता लोगों के लिए विकल्पों का विस्तार करती हैं। इसी के साथ हमने इसमें अन्तर्निहित चुनौतियों को भी यह कहते हुए रेखांकित किया कि मानव विकास के ये महत्वपूर्ण पहलू हमेशा एक साथ नहीं आते।

संवहनीयता और समता पर एकसाथ विचार करने का औचित्य

इस वर्ष हम पर्यावरणीय संवहनीयता और समता, जो वितरणात्मक न्याय (distributive justice) के लिए अपने सरोकार में मूलभूत रूप से समान हैं, के बीच के मिलन-बिन्दुओं की संभावनाओं को परखेंगे। हम संवहनीयता को इसलिए महत्व देते हैं क्योंकि भविष्य की पीढ़ियों को भी कम से कम वही अवसर मिलने चाहिए जो लोगों को आज उपलब्ध हैं। इसी तरह, सभी ग़ैर-बराबरी वाली प्रक्रियाएँ (processes) अन्यायपूर्ण हैं: लोगों के लिए बेहतर ज़िन्दगी के अवसर किसी ऐसे कारक से बाधित नहीं होने चाहिए जो उनके नियंत्रण से बाहर हों। असमानताएँ ख़ासतौर पर तब अधिक अन्यायपूर्ण होती हैं, जब एक समूह विशेष को लिंग, नस्ल या जन्मस्थान के आधार पर सुनियोजित ढंग से वंचित रखती हैं।

लगभग एक दशक पहले सुधीर आनंद और अमर्त्य सेन ने संवहनीयता और समता, दोनों पर साथ ध्यान दिये जाने के पक्ष में तर्क दिया था। उनका तर्क था कि ''यदि हम कई पीढ़ियों के बीच की समता की समस्या पर ध्यान दिये बिना एक ही पीढ़ी में होने वाली अ-समता में उलझे रहे तो यह सार्वभौमिकता के सिद्धांत का घोर उल्लंघन होगा।'' इसी तरह के मुद्दे (themes) 1987 के ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट, और 1972 में स्टाकहोम से लेकर 2002 में जोहान्सबर्ग तक की अनेक अंतरराष्ट्रीय घोषणाओं में से उभरे। इसके बावजूद आज संवहनीयता की तमाम बहसों में समानता को नज़रअंदाज़ कर इसे असम्बद्ध सरोकार के रूप में देखा जाता है। यह नज़रिया अपूर्ण तथा प्रतिकूल-परिणामी है।

कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ

मानव विकास लोगों की उन स्वतन्त्रताओं और क्षमताओं का विस्तार है जो उनके लिए महत्वपूर्ण हैं और जिन्हें महत्व देने के उनके पास वाजिब कारण हैं। इसका आशय विकल्पों के विस्तार से है। स्वतंत्रताएँ और क्षमताएँ मूलभूत आवश्यकताओं से अधिक व्यापक धारणाएँ हैं। एक 'अच्छे जीवन' के लिए अनेक साध्य (ends) आवश्यक हैं, जो आतंरिक व व्यावहारिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं—जैसे हम जैव विविधता या प्राकृतिक सौंदर्य को महत्वपूर्ण मान सकते हैं—और हमारा यह मानना इस बात से असम्बद्ध हो कि हमारे जीवन स्तर में इनका क्या योगदान है।

अभावों से जूझ रहे लोग मानव विकास की केन्द्रीय चिंता हैं। यह चिंता उन्हें भी शामिल करती है जो हमारी आज की गतिविधियों के भयावह परिणाम भविष्य में झेलेंगे। हम केवल सर्वाधिक संभावना वाले परिदृश्य (scenario) से ही चिंतित नहीं हैं, बल्कि उनसे भी, जिनके होने की संभावना अपेक्षाकृत कम तो है, लेकिन फिर भी है। ख़ासतौर पर तब, जब ये घटनाएँ ग़रीब और अरक्षित (vulnerable) लोगों के लिए विनाशकारी हों।

पर्यावरणीय संवहनीयता के अभिप्राय को लेकर चलने

वाली बहसें अक्सर इस बात पर केंद्रित होती हैं कि क्या मानव निर्मित पूँजी (human capital) प्राकृतिक संसाधनों की जगह ले सकती है—क्या मनुष्य की सृजनात्मकता प्राकृतिक संसाधनों की सीमितता का जवाब पहले की ही तरह खोज पायेगी। यह भविष्य में संभव होगा या नहीं, इसका पता नहीं। इसलिए यह विनाश के ख़तरे की संभावना को स्वीकारते हुए एक ऐसी अवस्थिति का पक्षधर है, जिसमें मूलभूत प्राकृतिक सम्पदा तथा उससे सम्बन्धित पारिस्थितिकीय सेवाओं का संरक्षण हो सके। यह परिप्रेक्ष्य विकास के मानवाधिकार आधारित दृष्टिकोण के साथ भी जुड़ा है। *संवहनीय मानव विकास वर्तमान में लोगों की प्रभावी स्वतंत्रताओं का विस्तार है, साथ ही, ऐसा सुसंगत प्रयास भी है जो भविष्य की पीढ़ियों को गंभीर समझौतों के साथ जीने की मजबूरियों से बचाये*। इस विचार के लिए ऐसी औचित्यपूर्ण सामाजिक विवेचनाओं का विशेष महत्व है, जो उन जोख़िमों को परिभाषित कर सकें जिन्हें उठाने के लिए समाज तैयार है (रेखांकन -1)।

संवहनीय मानव विकास वर्तमान में लोगों की प्रभावी स्वतंत्रताओं का विस्तार है, साथ ही, ऐसा सुसंगत प्रयास भी है जो भविष्य की पीढ़ियों को गंभीर समझौतों के साथ जीने की मजबूरियों से बचाये

पर्यावरणीय संवहनीयता और समता, दोनों हासिल करने के साझा प्रयास में यह ज़रूरी नहीं है कि दोनों हमेशा एक-दूसरे को मज़बूत करने वाले ही हों। कई अवसरों पर दोनों के बीच कहीं समझौते करने पड़ेंगे। पर्यावरण को सुधारने के उपाय समता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं—उदाहरण के लिए अगर वे विकासशील देशों की आर्थिक प्रगति को बाधित करें। यह रिपोर्ट नीतियों के समवेत प्रयासों को दर्शाती है। साथ ही, यह भी स्वीकारती है कि ये प्रभाव हर जगह समान रूप से लागू नहीं होते, और यह कि सन्दर्भ समझना बहुत आवश्यक है।

यह ढाँचा इन दो लक्ष्यों के बीच सकारात्मक संगतियों की पहचान करने और इनके बीच सम्भाव्य समझौतों पर विशेष ध्यान देने को प्रोत्साहित करता है। हम यह परखेंगे कि समाज कैसे परस्पर लाभदायक समाधानों को क्रियान्वित करें जो संवहनीयता, समता और मानव विकास को बढ़ावा दें।

रेखांकन 1

संवहनीयता और समता के बीच नीतिगत संगतियाँ और समझौतों (trade-offs) के उदाहरण

यह रेखांकन इन दो लक्ष्यों के बीच की सकारात्मक संगतियों को पहचानने और इनके बीच सम्भाव्य समझौतों पर विशेष ध्यान देने को प्रोत्साहित करता है।

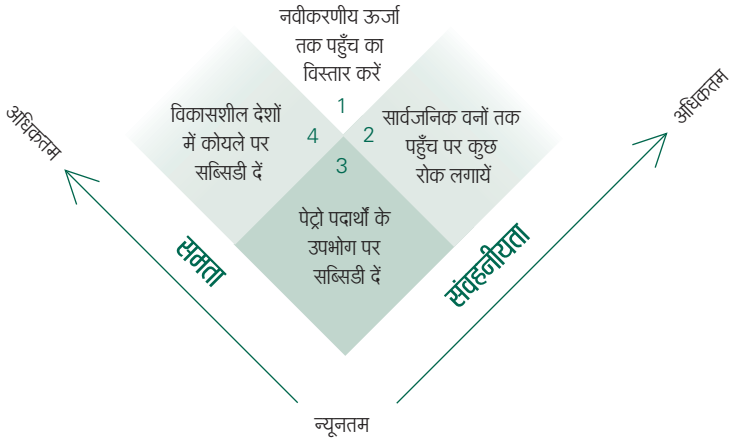

प्रतिमान और रुझान, प्रगति और संभावनाएँ

लगातार मिल रहे साक्ष्य दुनिया भर में बड़े पैमाने पर हो रहे पर्यावरणीय क्षरण और भविष्य में इसके बद्तर होने की आशंका की ओर इशारा कर रहे हैं। चूँकि भविष्य के परिवर्तन अनिश्चित हैं, हम तमाम पूर्वानुमानों को परखेंगे और मानव विकास के लिए इनसे उपजी अंतर्दृष्टियों पर विचार करेंगे।

हमारा प्रस्थान बिन्दु पिछले कई दशकों में मानव विकास के क्षेत्र में हुई अभूतपूर्व प्रगति है, जो 2010 की एच.डी.आर. का केन्द्रीय विषय भी रहा है—लेकिन इसमें तीन विचारणीय जटिलताएँ हैं:

- आय बढ़ने के साथ कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरणीय संकेतकों में ह्रास हुआ है। जैसे, कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन, मिट्टी, जल तथा वनों की गुणवत्ता में हानिकारक बदलाव हुए ।
- स्वास्थ्य और शिक्षा सम्बन्धी उपलब्धियों के बीच अंतर कम होने के बावजूद आय के वितरण की स्थिति दुनिया के अधिकतर देशों में बद्तर हुई है।
- बावजूद इसके कि आमतौर पर सशक्तीकरण के साथ मानव विकास सूचकांक (एच.डी.आई.) में बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति होती है, लेकिन दोनों के बीच के इस रिश्ते में काफ़ी उतार-चढ़ाव रहा है।

इस रिपोर्ट के लिए किये गये सांख्यिकीय पूर्वानुमान (simulations) बताते हैं कि 'पर्यावरणीय चुनौती' के परिदृश्य में और सन्दर्भ रेखा (baseline) की तुलना में वर्ष 2050 तक एच.डी.आई. 8% (और दक्षिण एशिया तथा सब-सहारा अफ्रीकी देशों में 12%) कम हो जायेगी। यह एक ऐसे 'पर्यावरणीय चुनौती' के परिदृश्य में होगा जिसमें ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कृषि उत्पादन पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव, साफ़ पेयजल और बेहतर साफ़-सफ़ाई की उपलब्धता में कमी और प्रदूषण की समस्याएँ शामिल हैं। इससे भी अधिक प्रतिकूल 'पर्यावरणीय आपदा' का ऐसा भी परिदृश्य है जिसमें व्यापक निर्वनीकरण, भू-क्षरण, जैव विविधता में बेहिसाब कमी और मौसम की अनिश्चितता की तीखी मार देने वाली घटनाओं की आशंका व्यक्त की गयी है। इस परिदृश्य के अनुसार वैश्विक एच.डी.आई. अनुमानित सन्दर्भ रेखा से क़रीब 15% तक कम हो जायेगा।

रेखांकन 2 उन जोख़िमों और नुक्सानों का स्तर बताता है, जिन्हें 2050 में हमारे नाती-पोतों को झेलना पड़ेगा, यदि हमने वर्तमान रुझान को रोकने या पलटने के लिए कुछ नहीं किया। यह पर्यावरणीय आपदा का परिदृश्य

2050 के पहले ही विकासशील देशों को एक निर्णायक मोड़ पर ला खड़ा करने का संकेत करता है—जिस दोराहे से विकासशील देश एच.डी.आई. उपलब्धियों में अमीर देशों की ही दिशा में बढ़ने की जगह उलट दिशा में बढ़ने लगेंगे।

ये अनुमान बताते हैं कि कई मामलों में पर्यावरणीय क्षरण के दुष्प्रभाव सबसे अधिक वंचित लोग सहते हैं और आगे भी सहेंगे, फिर चाहे समस्याओं को बढ़ाने में उनका योगदान न के बराबर क्यों न हो। उदाहरण के लिए निम्न एच.डी.आई. वाले देश जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे कम ज़िम्मेदार हैं लेकिन उनके यहाँ बारिश में सबसे अधिक कमी तथा इसकी अनिश्चितता में सर्वाधिक वृद्धि हुई है (रेखांकन -3)। इसका कृषि उत्पादन और आजीविका पर सीधा असर पड़ा है।

अधिक ऊर्जा-सघन गतिविधियों—कार चलाने, घरों तथा व्यवसायों में शीतलन तथा ऊष्मन विधियों के उपयोग, प्रसंस्करित तथा डिब्बाबंद भोजन के उपभोग—के कारण निम्न, मध्यम और उच्च एच.डी.आई. वाले देश मिलकर भी उच्च एच.डी.आई. वाले देशों की तुलना में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन काफ़ी कम करते हैं। अति उच्च एच.डी.आई. वाले देशों के औसत व्यक्ति निम्न, मध्यम या उच्च एच.डी.आई. देशों के औसत निवासियों की तुलना में चार गुना अधिक कार्बन डाई ऑक्साइड और लगभग दोगना अधिक मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन में योगदान करते हैं और यह उत्सर्जन निम्न एच.डी.आई. देशों के एक व्यक्ति द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाई ऑक्साइड की तुलना में लगभग तीस गुना अधिक है। ब्रिटेन का एक औसत निवासी दो महीने में उतनी ही ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में योगदान करता है जितना एक निम्न एच.डी.आई. वाले देश का निवासी पूरे वर्ष में। और कतर—सर्वाधिक प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वाला देश—का एक औसत निवासी 10 दिन में ही उतने उत्सर्जन में योगदान कर देता है। हालाँकि यह मान उपभोग के साथ ही उस उत्पादन को भी प्रदर्शित करता है जिसका उपभोग अन्यत्र होता है।

बावजूद इसके कि 1970 से अब तक उत्सर्जनों की वृद्धि का तीन चौथाई निम्न, मध्यम तथा उच्च एच.डी.आई. वाले देशों में हुआ है, ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा अति उच्च एच.डी.आई. वाले देशों में अब भी बहुत अधिक है। और ऐसा तब है जबकि यह गणना इस तथ्य को नज़रअंदाज़ करती है कि कार्बन-सघन उत्पादन अपेक्षाकृत ग़रीब देशों में स्थानांतरित हो गया है, जहाँ से फिर ये उत्पाद अधिकतर अमीर देशों को निर्यात होते हैं।

दुनिया भर में एच.डी.आई. का बढ़ना पर्यावरणीय क्षरण से सम्बद्ध रहा है—यद्यपि इस नुक्सान की जड़ काफ़ी हद तक आर्थिक प्रगति में ढूँढ़ी जा सकती है। चौथे रेखांकन में पहले और तीसरे पैनल के आपसी विरोधाभास को देखें। पहला पैनल दिखाता है कि अधिक आय वाले देशों में आमतौर पर अधिक कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जित होती है। लेकिन तीसरा पैनल उत्सर्जनों और एच.डी.आई.

रेखांकन 2

2050 तक मानव विकास पर पर्यावरणीय जोख़िमों के संभावित प्रभावों का परिदृश्य

एच.डी.आई.

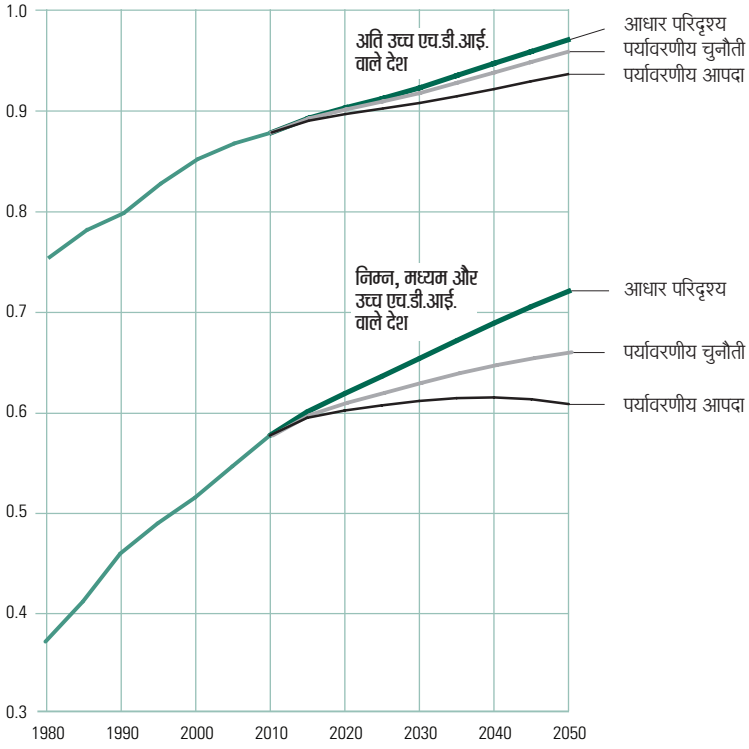

नोटः परिदृश्यों की व्याख्या के लिए आलेख देखें

स्रोतः एच.डी.आर.ओ. गणनाएँ एच.डी.आर.ओ. के आँकड़ों और बी. ह्यूजेज़, एम. इरफ़ान, जे. मोयर, डी. रॉथमैन, और जे. सॉलोर्ज़ानो, 2011, "फ़ोरकास्टिंग दि इपैक्ट्स ऑफ़ एन्वायरन्मेंटल कन्स्ट्रेंट्स ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट", ह्यूमन डेवलपमेंट रिसर्च पेपर, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, न्यूयॉर्क पर आधारित हैं, जिनमें इंटरनेशनल फ्यूचर्स, संस्करण 6.42 से उत्पन्न पूर्वानुमानों की मदद ली गयी है।

के स्वास्थ्य तथा शिक्षा वाले संघटकों के बीच कोई सहसम्बन्ध नहीं दिखाता। यह परिणाम सांकेतिक (intuitive) हैः जिन गतिविधियों से वातावरण में कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जित होती है वे वस्तुओं के उत्पादन से जुड़ी हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा उपलब्ध कराने से नहीं। ये परिणाम कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन और एच.डी.आई. संघटकों के बीच के रिश्ते की अ-रेखीय (non-linear) प्रवृत्ति भी बताते हैं—निम्न एच.डी.आई. मान पर इनके बीच मामूली या बिल्कुल भी निर्भरता नहीं होती है, लेकिन एच.डी.आई. बढ़ने पर एक ऐसा 'अनिवर्ती बिन्दु' (वह बिन्दु जहाँ से फिर पीछे न लौटा जा सके, यानी, tipping point) आता है, जिसके बाद कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन और आय के बीच मज़बूत सकारात्मक सह-सम्बन्ध (correlation) पाया जाता है।

जिन देशों में एच.डी.आई. में तेज़ी से सुधार हुआ है उन देशों में प्रति व्यक्ति कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन में भी तेज़ी से वृद्धि देखी गयी है। यह बदलाव किसी तात्कालिक अंतर्सम्बन्ध (snapshot relationship) की जगह एक लंबे दौर में देखे जाने पर स्पष्ट करता है कि आज के विकास की परिणति के रूप में कल के लिए क्या उम्मीद

रेखांकन 3

बढ़ते तापमान और घटती वर्षा

एच.डी.आई. समूह के सापेक्ष जलवायु परिवर्तनशीलता (variability) के स्तर और उसमें बदलाव

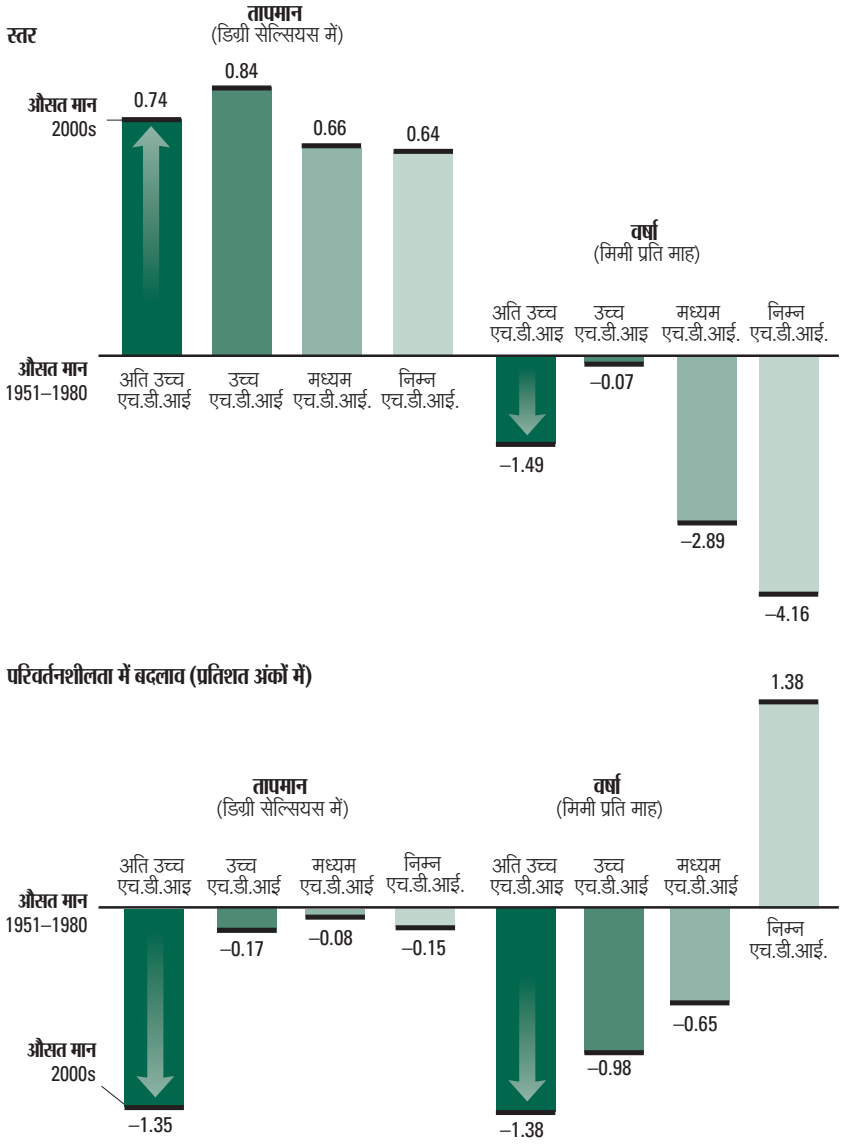

नोटः परिवर्तनशीलता में बदलाव 1951-1980 तथा 2000 के दशक के परिवर्तन गुणांकों का अंतर है, जो 1951-1980 की औसत जनसंख्या से भारित (weighted) है।

स्रोतः एच.डी.आर.ओ. गणनाएँ, डेलावेयर विश्वविद्यालय के आँकड़ों पर आधारित

की जानी चाहिए। ग़ौरतलब है कि आय में बदलाव ही इस रुझान को प्रेरित करते हैं।

लेकिन ये सम्बन्ध सभी पर्यावरणीय संकेतकों के लिए लागू नहीं होते। उदाहरण के लिए, हमारी विवेचना में एच.डी.आई. और निर्वनीकरण के बीच केवल एक कमज़ोर सकारात्मक सह-सम्बन्ध मिलता है। कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन दूसरे पर्यावरणीय ख़तरों से अलग क्यों है? हमारा प्रस्ताव है कि जहाँ पर्यावरण और जीवन की गुणवत्ता के बीच सीधा सम्बन्ध है, जैसे कि प्रदूषण में, तब पर्यावरणीय उपलब्धियाँ अक्सर विकसित देशों में अधिक हैं; और जहाँ यह सम्बन्ध अस्पष्ट है, वहाँ उनका प्रदर्शन कमज़ोर है। पर्यावरणीय जोख़िमों और एच.डी.आई. के सम्बन्ध पर विचार करते हुए हमें तीन सामान्य निष्कर्ष दिखाई देते हैं–

- पर्यावरणीय घरेलू अभाव–घर के भीतर का वायु प्रदूषण, साफ़ पानी तथा बेहतर साफ़-सफ़ाई की अपर्याप्त सुलभता–निम्न एच.डी.आई. वाले देशों में अधिक तीव्र हैं और एच.डी.आई. के बढ़ने के साथ ये अभाव घटते हैं।
- समुदाय पर प्रभाव डालने वाले पर्यावरणीय जोख़िम–जैसे शहरी वायु प्रदूषण–विकास के साथ पहले बढ़ते और फिर घटते हुए प्रतीत होते हैं; कुछ विशेषज्ञों की राय में एक उलटे U के आकार का वक्र (inverted U-shaped curve) इस रिश्ते को प्रदर्शित करता है।
- भूमंडलीय प्रभाव वाले पर्यावरणीय जोख़िम–जैसे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन–आमतौर पर मानव विकास सूचकांक के साथ बढ़ते हैं।

एच.डी.आई. अपने आप में इन तब्दीलिओं का वास्तविक उत्प्रेरक नहीं है। आय और आर्थिक प्रगति उत्सर्जनों में एक ऐसी अहम भूमिका निभाते हैं जिसकी विवेचना की आवश्यकता है–लेकिन इनके बीच का सम्बन्ध भी निश्चयात्मक (deterministic) नहीं है। और अन्य व्यापक शक्तियों की आपसी क्रिया-प्रतिक्रिया जोख़िमों के ढर्रे को बदल देती है। उदाहरण के लिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार देशों को उन वस्तुओं का उत्पादन बाहर से करवाने की अनुमति देता है जो पर्यावरण को नुक्सान पहुँचाते हैं; प्राकृतिक संसाधनों के बड़े पैमाने पर व्यावसायिक उपयोग का प्रभाव जीवन-निर्वाह के लिए किये जाने वाले उपयोग से बिल्कुल अलग है, और ग्रामीण तथा शहरी पर्यावरणीय परिदृश्यों में अन्तर है। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, नीतियाँ तथा राजनीतिक सन्दर्भ अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ये प्रतिमान अपरिहार्य नहीं हैं। अनेक देशों ने एच.डी.आई. और समता व पर्यावरणीय संवहनीयता, दोनों में ही उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। सकारात्मक संगतियों पर अपने फ़ोकस की दिशा में आगे बढ़ते हुए हम उन देशों की पहचान के लिए एक बहुआयामी रणनीति का प्रस्ताव करते हैं, जिन्होंने समता को बढ़ावा देने, एच.डी.आई. बढ़ाने, घरेलू वायु प्रदूषण घटाने और स्वच्छ जल की सुलभता बढ़ाने में अपने क्षेत्रीय समकक्षों (peers) की तुलना में बेहतर काम किया है और जिन्होंने क्षेत्रीय तथा भूमंडलीय स्तर पर पर्यावरणीय संवहनीयता के मुद्दे पर सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है (सारणी 1)। पर्यावरणीय संवहनीयता का आकलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, जल उपयोग और निर्वनीकरण के आधार पर किया गया है। अपूर्ण आँकड़ों तथा कुछ तुलनात्मकता सम्बन्धी अनिश्चितता के कारण ये परिणाम स्पष्ट संकेतक न होकर दृष्टान्तात्मक (illus-

रेखांकन 4

प्रति व्यक्ति कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन का आय से जुड़ाव सकारात्मक और मज़बूत है, एच.डी.आई. के साथ सकारात्मक है और शिक्षा तथा स्वास्थ्य से इसका कोई जुड़ाव नहीं है

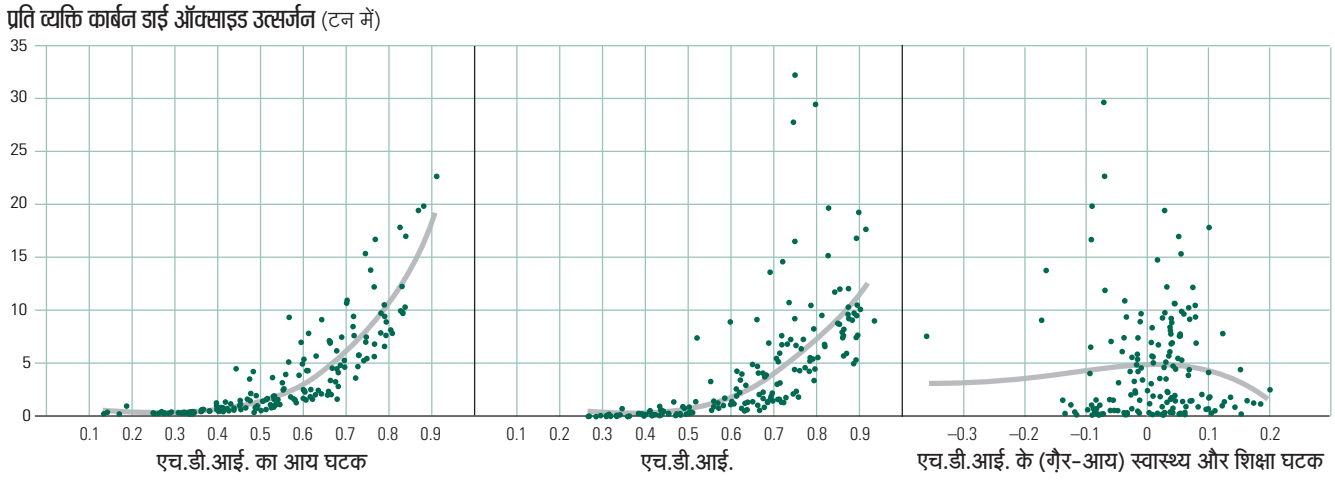

नोटः आँकड़े 2007 के हैं
स्रोतः एच.डी.आर.ओ. के आँकड़ों पर आधारित एच.डी.आर.ओ. गणनाएँ

trative) हैं। केवल एक देश, कोस्टारिका, ने हर मानदंड पर अपने क्षेत्रीय माध्य (median) मान से बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि अन्य तीन श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले देश भिन्न आयामों पर अ-सम (uneven) प्रदर्शन करते हैं। स्वीडन क्षेत्रीय तथा भूमंडलीय औसत की तुलना में अपनी उच्च पुनर्वानिकी (reforestation) दर के कारण उल्लेखनीय है।

हमारी सूची दर्शाती है कि क्षेत्रों, विकास की अवस्थाओं और संरचनात्मक अभिलक्षणों की भिन्नताओं के बावजूद देश ऐसी नीतियाँ लागू कर सकते हैं जो पर्यावरणीय संवहनीयता, समता और एच.डी.आई. में शामिल मानव विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं के अनुकूल हों। हम स्थानीय परिस्थितियों तथा सन्दर्भों के महत्व को रेखांकित करते हुए ऐसी नीतियों तथा कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे जो सफलता से सम्बद्ध हैं।

मोटे तौर पर देखें तो हाल के दशकों के पर्यावरणीय रुझान अनेक मोर्चों पर गिरावट प्रदर्शित करते हैं। इनका मानव विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। और ख़ासतौर से उन लाखों लोगों पर, जो अपनी आजीविका के लिए सीधे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं।

- भूमंडलीय स्तर पर, लगभग 40% प्रतिशत ज़मीन भू-क्षरण, उर्वरकता में कमी और अत्यधिक चराई के कारण ख़राब हो गयी है। भू-उत्पादकता कम हो रही है, जिससे पैदावार को अनुमानित हानि, सबसे प्रतिकूल परिदृश्य में, 50% तक है।
- जल का 70 से 85 फ़ीसदी उपयोग कृषि में होता है, और लगभग 20% वैश्विक अनाज उत्पादन में जल का असंवहनीय उपयोग होता है जो भविष्य के कृषि विकास के लिए ख़तरे की घंटी है।
- निर्वनीकरण एक बहुत बड़ी चुनौती है। 1990 से 2010 के बीच लैटिन अमेरीका, कैरीबियन और सब-सहारा अफ़्रीकी देशों में सबसे अधिक जंगलों की हानि हुई, इसके बाद अरब देशों का नंबर है (देखें रेखांकन – 5)। अन्य क्षेत्रों ने वनाच्छादन के क्षेत्र में मामूली बढ़त हासिल की है।
- मरुस्थलीकरण का ख़तरा उस शुष्क भू-भाग पर मँडरा रहा है, जिसमें दुनिया की आबादी का क़रीब

सारणी 1

हाल के आँकड़ों के अनुसार समता व मानव विकास के क्षेत्र में सबसे बेहतर प्रदर्शक

	वैश्विक ख़तरे		स्थानीय प्रभाव			समता एवं मानव विकास	
देश	ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन	निर्वनीकरण	जल प्रयोग	पानी की सुलभता	वायु प्रदूषण	एच.डी.आई. (क्षेत्रीय माध्यिका का प्रतिशत)	कुल क्षति (क्षेत्रीय माध्यिका का प्रतिशत)
कोस्टारिका	✔	✔	✔	✔	✔	104	77
जर्मनी		✔	✔	✔	✔	103	91
फ़िलीपीन्स	✔	✔		✔	✔	103	89
स्वीडन		✔	✔	✔	✔	102	70

नोटः ये सभी देश विस्तृत रिपोर्ट (अध्याय 2, नोट 80) में परिभाषित पर्यावरण के वैश्विक ख़तरों के तमाम पैमानों पर खरे उतरते हैं, अपने क्षेत्र के समकक्षों की तुलना में मानव विकास और असमानता के आयामों में क्षेत्रीय माध्य मानों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं और स्थानीय प्रभावों के सन्दर्भ में भी क्षेत्रीय माध्य मान से बेहतर प्रदर्शन करते हैं।

रेखांकन 5

क्षेत्रवार वनोन्मूलन, पुनर्वनीकरण और वनीकरण

क्षेत्रवार वनाच्छादन का अंश और परिवर्तन की दर, 1990-2010 (मिलियन वर्ग किलोमीटर में)

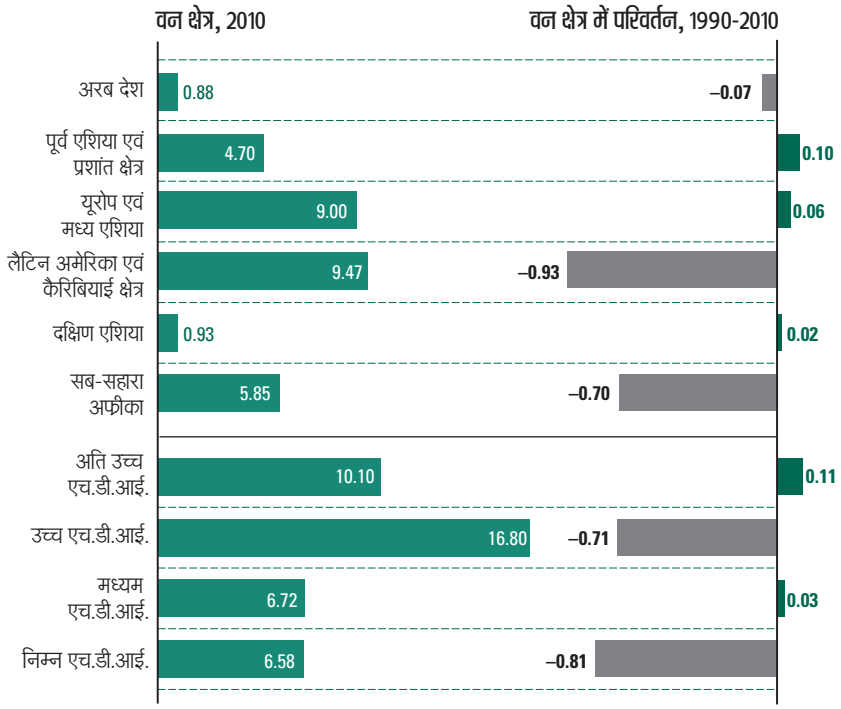

स्रोतः विश्व बैंक के 2011 के आँकड़ों, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडीकेटर्स, वाशिंगटन डी.सी.: वर्ल्ड बैंक पर आधारित एच.डी.आर.ओ. गणनाएँ

एक तिहाई हिस्सा रहता है। कुछ क्षेत्र ख़ासतौर पर अ-रक्षित हैं जैसे सब-सहारा अफ़्रीका, जहाँ शुष्क भूमि अति संवेदनशील है और परिवर्तनों के अनुकूल बदलने की लोच उनमें बहुत कम है।

प्रतिकूल पर्यावरणीय कारक आने वाले दशकों में दुनिया भर में खाद्य पदार्थों की क़ीमतों में 30-50% की बढ़ोत्तरी और क़ीमतों में अस्थिरता ला सकते हैं, जिसके ग़रीब परिवारों पर भयावह परिणाम होंगे। सबसे ज़्यादा ख़तरा उन 1.3 अरब लोगों पर है, जो कृषि, मछलीपालन, वानिकी, शिकार और एकत्रण जैसे कामों में लगे हैं। पर्यावरणीय क्षरण और जलवायु परिवर्तन के बोझ का प्रभाव विभिन्न समूहों में ग़ैर-बराबरी बढ़ाने वाला होने की संभावना है और इसके अनेक कारण हैं:

- अनेक ग्रामीण लोग अपनी आय के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत अधिक निर्भर हैं। यहाँ तक कि जो लोग सामान्यतया ऐसी गतिविधियों में संलग्न नहीं होते, वे भी मुश्किल वक़्त का सामना करने के लिए ऐसा कर सकते हैं।
- पर्यावरणीय क्षरण किस तरह लोगों को प्रभावित करेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि लोग प्राकृतिक संसाधनों के कुल-जमा उत्पादक (net producer) हैं या कुल-जमा उपभोक्ता, वे जीवन निर्वाह के लिए उत्पादन करते हैं या बाज़ार के लिए, और इस पर भी कि वे कितनी शीघ्रता से इन गतिविधियों में अदला-बदली कर सकते हैं तथा अपनी आजीविका के विकल्पों का विस्तार कर सकते हैं।
- आज क़रीब 35 करोड़ लोग, जिनमें ज़्यादातर ग़रीब हैं, जंगलों में या जंगलों के क़रीब रहते हैं और उन्हीं पर अपने निर्वाह तथा आय के लिए निर्भर हैं। जंगलों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर पाबंदी, दोनों ही ग़रीबों को नुक़सान पहुँचा सकते हैं। अनेक देशों से प्राप्त साक्ष्य सुझाते हैं कि औरतें आमतौर पर पुरुषों की तुलना में जंगलों पर अधिक निर्भर रहती हैं क्योंकि औरतों के पास काम-धंधे के विकल्प कम होते हैं, वे कम गतिशील होती हैं और जलाऊ लकड़ी एकत्र करने की सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी उन पर ही होती है।
- लगभग 4.5 करोड़ लोग, जिनमें कम से कम 60 लाख औरतें हैं, आजीविका के लिए मछली पकड़ते हैं और बहुत अधिक मछली पकड़ने तथा जलवायु परिवर्तन से उन्हें ख़तरा है। ख़तरे के प्रति उनकी अ-रक्षितता दोहरी है: जिन देशों पर सबसे ज़्यादा ख़तरा है, वही देश आहारीय प्रोटीन, आजीविका और निर्यात के लिए सबसे अधिक मछली पर निर्भर हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण प्रशांत महासागर द्वीपों के आसपास मछलियों के भण्डार में तेज़ी से कमी होने की संभावना है जबकि कुछ उत्तरी ध्रुव के क्षेत्रों, जिनमें अलास्का, ग्रीनलैण्ड, नार्वे तथा रूसी फेडरेशन शामिल हैं, के लाभान्वित होने की संभावना है।

जिस हद तक ग़रीब देशों में महिलाएँ एक विषम अनुपात में जीवन निर्वाह के लिए खेती तथा पानी इकट्ठा करने के काम में लगी हैं, पर्यावरणीय क्षरण के उन पर अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका रहती है। छोटे द्वीपीय विकासशील देशों में, ध्रुवीय क्षेत्रों और अधिक ऊँचाई पर रहने वाले अनेक आदिम-रहवासी (indigenous) समूह भी प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहते हैं और ऐसे पारिस्थितिकीय तंत्रों में रहते हैं जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति कुछ अधिक ही अरक्षित हैं। साक्ष्य बताते हैं कि पारंपरिक पद्धतियाँ प्राकृतिक संसाधनों को बचा सकती हैं, लेकिन फिर भी ऐसे देशज ज्ञान की अक्सर उपेक्षा होती है या फिर उसे महत्वहीन माना जाता है।

जलवायु परिवर्तन का किसानों पर प्रभाव फसल, क्षेत्र और मौसम पर निर्भर करता है जो कि एक गहरी स्थानीय विवेचना के महत्व को रेखांकित करता है। ये प्रभाव घरेलू स्तर पर होने वाले उत्पादन और उपभोग के तरीकों, संसाधनों तक पहुँच, ग़रीबी के स्तर और हालात का सामना कर पाने की क्षमता के आधार पर अलग-अलग होंगे। कुल मिलाकर, 2050 तक जलवायु परिवर्तन के

सिंचित और वर्षा पर निर्भर फसलों पर जैव-भौतिकी प्रभाव नकारात्मक होने की संभावना है—और सबसे बुरे हाल निम्न एच.डी.आई. वाले देशों में होंगे।

रिश्ते की कड़ियों की पहचान

भूमंडलीय स्तर पर पर्यावरण तथा समता के महत्वपूर्ण मिलन बिंदुओं के निहितार्थों के आलोक में हम सामुदायिक और पारिवारिक स्तर पर इनके बीच के कार्यशील रिश्तों को परखने का प्रयास करेंगे। हम उन देशों और समूहों को भी रेखांकित करेंगे जिन्होंने लैंगिक भूमिकाओं को बदल कर और सशक्तीकरण द्वारा इन रिश्तों के प्रचलित प्रतिमानों को तोड़ा है।

एक महत्वपूर्ण विषयः सर्वाधिक सुविधावंचित लोग अभावों का दोहरा बोझ उठाते हैं। पर्यावरणीय क्षरण के व्यापक प्रभावों के प्रति अधिक अरक्षित होने के साथ ही साथ उन्हें घरेलू वायु प्रदूषण, गंदे पानी और बद्तर साफ़-सफ़ाई से उपजे तात्कालिक परिवेशगत पर्यावरणीय ख़तरों से भी जूझना होता है। हमारा बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (एम.पी.आई.), जो 2010 की एच.डी.आर. में प्रस्तावित हुआ और इस साल 109 देशों के लिए जिसकी गणना की गयी है, वह इन तमाम वंचितताओं की और क़रीबी व्याख्या करते हुए यह परखने में मदद करता है कि ये वंचनाएँ कहाँ सबसे तीखी हैं।

एम.पी.आई. (बहुआयामी निर्धनता सूचकांक) वंचितों की संख्या तथा उनकी वंचितता की प्रबलता, दोनों पर ध्यान देते हुए स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के आयामों में गंभीर अभावों की माप करता है (रेखांकन-6)। इस साल हमने बहुआयामी रूप से ग़रीब लोगों के बीच पर्यावरणीय क्षरण से उपजे अभावों की व्यापकता परखी है, साथ ही यह भी देखा है कि घरेलू स्तर पर भी ये प्रभाव कैसे ओवरलैप करते हैं—और यही एम.पी.आई. में एक नयी बात है।

ग़रीबी पर केंद्रित दृष्टिकोण की बदौलत हम आधुनिक रसोई ईंधन, साफ़ पानी और मूलभूत साफ़-सफ़ाई की सुलभता के सन्दर्भ में पर्यावरणीय वंचना को देख पाते हैं। अपने आप में महत्वपूर्ण ये बेहद तीखी वंचनाएँ मानव अधिकारों का बड़ा उल्लंघन हैं। इन वंचितताओं का ख़ात्मा न केवल उच्च स्तर की क्षमताओं को बढ़ायेगा, वरन लोगों की चयन की संभावनाओं का विस्तार कर मानव विकास को आगे बढ़ा सकता है।

विकासशील देशों में हर दस में से कम से कम छह लोग इन वंचनाओं में से किसी एक का अनुभव करते हैं और हर दस में से चार इनमें से दो या अधिक वंचनाएँ झेलते हैं। ये वंचनाएँ ख़ासतौर से बहुआयामी निर्धनों में बेहद तीखी हैं, जिनमें दस में से नौ कम से कम एक वंचना तो झेलते ही हैं। अधिकतर एकाधिक वंचनाएँ झेलते हैंः दस में से आठ बहुआयामी निर्धन इनमें से दो या अधिक वंचितताएँ सहते हैं और लगभग हर तीन में से एक (29%) इन तीनों सुविधाओं से महरूम है। ये पर्यावरणीय वंचनाएँ बहुआयामी ग़रीबी को असंगत रूप

रेखांकन 6

बहुआयामी निर्धनता सूचकांक— सर्वाधिक वंचितों पर फ़ोकस

से बढाती हैं, जिनका एम.पी.आई. में योगदान 20% है — जो कि सूचकांक में उनके 17% के सांख्यिकीय महत्व (weight) से अधिक है। ज़्यादातर विकासशील देशों में रसोई ईंधन की वंचितता सर्वाधिक है जबकि कई अरब देशों में पानी की कमी सबसे बड़ी समस्या है।

पर्यावरणीय वंचनाओं को बेहतर तरीके से समझने के लिए, हमने ग़रीबी के स्तरों के अनुसार इसके प्रतिमानों की विवेचना की। देशों को दो तरह से क्रमबद्ध किया—एक पर्यावरणीय वंचना का सामना कर रहे बहुआयामी निर्धनों के प्रतिशत के आधार पर तथा तीनों पर्यावरणीय वंचनाओं का सामना कर रहे बहुआयामी निर्धनों के प्रतिशत के अनुसार। पर्यावरणीय वंचना वाले लोगों का प्रतिशत एम.पी.आई. बढ़ने के साथ बढ़ जाता है, लेकिन इस मुख्य रुझान के इर्द-गिर्द काफ़ी उतार-चढ़ाव है। सारणी-2 दस ऐसे देशों की पहचान करती है जिनमें उनके बहुआयामी निर्धनों के बीच सबसे कम पर्यावरणीय वंचनाएँ हैं, जो कि उनके एम.पी.आई. को नियंत्रित करती हैं (बायाँ कॉलम)। ऐसे देश, जिनमें कम से कम एक पर्यावरणीय वंचना झेलने वाले ग़रीब लोगों का प्रतिशत सबसे कम है, मुख्यतः अरब और लैटिन अमेरीकी तथा कैरेबियन क्षेत्र में हैं (पहले 10 में से 7)।

सारणी 2

वे 10 देश जिनमें बहुआयामी निर्धन लोग न्यूनतम पर्यावरणीय वंचितता झेलते हैं, 2000-2010 के दौर में उपलब्ध अद्यतन आँकड़ों के आधार पर

कम से कम एक वंचितता सहने वाले बहुआयामी निर्धनों के न्यूनतम प्रतिशत वाले देश	तीनों वंचितताएँ सहने वाले बहुआयामी निर्धनों के न्यूनतम प्रतिशत वाले देश
ब्राज़ील	बांग्लादेश
गयाना	**पाक़िस्तान**
जिबूती	गैम्बिया
यमन	नेपाल
इराक	भारत
मोरक्को	भूटान
पाक़िस्तान	**जिबूती**
सेनेगल	**ब्राज़ील**
कोलंबिया	**मोरक्को**
अंगोला	**गयाना**

नोटः मोटे अक्षरों में दिख रहे देश दोनों सूचियों में हैं

स्रोतः एच.डी.आर.ओ. स्टाफ़ के आकलन, एम.पी.आई. के असम्बद्ध आँकड़ों के आधार पर

जिन देशों में सभी तीन पर्यावरणीय वंचना झेलने वाले बहुआयामी निर्धनों का प्रतिशत सबसे कम है, उनमें से अच्छा प्रदर्शन करने वाले देश दक्षिण एशिया में संकेंद्रित हैं– पहले 10 में से 5 (देखें सारणी 2, दाहिना कॉलम)। कई दक्षिण एशियाई देशों ने कुछ पर्यावरणीय वंचनाओं– मुख्य रूप से पीने के पानी की सुलभता की वंचना–को घटाया है, बावजूद इसके कि दूसरी वंचनाएँ अब भी तीक्ष्ण हैं। और पाँच देश अच्छा प्रदर्शन करने वाली दोनों सूचियों में हैं–न केवल उनकी पर्यावरणीय ग़रीबी बल्कि उसकी तीव्रता भी तुलनात्मक रूप से कम है।

इन संकेतकों के मापदण्डों पर बेहतर प्रदर्शन अनिवार्य रूप से पर्यावरणीय जोख़िमों और क्षरण की पहचान अधिक व्यापक सन्दर्भों में नहीं करता, जैसे बाढ़ के ख़तरे की पहचान नहीं करता। साथ ही, यह भी साफ़ है कि ग़रीब, जिन पर पर्यावरणीय ख़तरों का सीधा और अधिकाधिक प्रभाव पड़ता है, उन्हीं को प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरणीय क्षरण की मार सबसे अधिक झेलनी होती है। इसी प्रतिमान की और गहराई से जाँच करते हुए हम एम.पी.आई. और जलवायु परिवर्तन से उपजने वाले दबाव के आपसी सम्बन्धों को परखेंगे। 15 देशों के राष्ट्रीय स्तर पर परिभाषित 130 प्रशासनिक क्षेत्रों के लिए हम क्षेत्रवार एम.पी.आई. की तुलना वर्षण और तापमान से करते हैं। कुल मिलाकर, इन देशों के सबसे ग़रीब क्षेत्र और स्थान अधिक गर्म होते दिखते हैं लेकिन तुलनात्मक रूप से न तो ज़्यादा नम या सूखे होते दिखते हैं– ऐसा कोई परिवर्तन नहीं दिखता जो आय की ग़रीबी पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की पड़ताल से उभरे साक्ष्यों से सुसंगत हो।

आय तथा आजीविका से कहीं आगे बढ़कर पर्यावरणीय क्षरण स्वास्थ्य, शिक्षा और ख़ुशहाली के दूसरे पहलुओं पर असर डालता है और लोगों की क्षमताओं को कई तरीकों से हमेशा के लिए जड़ कर देता है

रेखांकन 7

पर्यावरणीय जोख़िमों से जोड़ी जा सकने वाली मौतें उच्च एम.पी.आई. से सम्बद्ध हैं

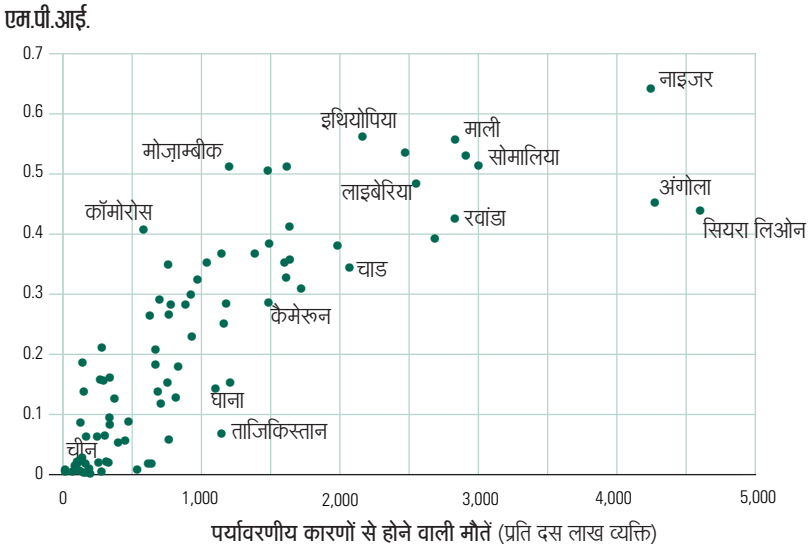

नोटः इसमें अति उच्च एच.डी.आई. वाले देश शामिल नहीं हैं। देशों में सर्वेक्षण अलग-अलग वर्षों में किये गये हैं। विस्तृत विवरण के लिए सपूर्ण रिपोर्ट की सांख्यिकीय तालिका 5 देखें।

स्रोतः ए. प्रूस ओस्टिन, आर. बॉस, एफ़ गोर, जे. बाट्रेम, 2008, सेफ़र वाटर बैटर हैल्थ, कॉस्ट्स, बैनिफ़िट्स एण्ड सस्टेनेबिलिटी ऑफ़ इंटरवेंशन्स टु प्रोटेक्ट एण्ड प्रमोट हैल्थ, जिनीवाः वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइज़ेशन

मानव विकास के चुनींदा पहलुओं को पर्यावरणीय ख़तरे

आय तथा आजीविका से कहीं आगे बढ़कर पर्यावरणीय क्षरण स्वास्थ्य, शिक्षा और ख़ुशहाली के दूसरे पहलुओं पर असर डालता है और लोगों की क्षमताओं को कई तरीकों से हमेशा के लिए जड़ कर देता है।

ख़राब पर्यावरण और स्वास्थ्य –एक-दूसरे को छा लेती वंचनाएँ

बाहरी तथा घरेलू वायु प्रदूषण, गंदा पानी और अपरिष्कृत साफ़-सफ़ाई से होने वाली बीमारी का बोझ ग़रीब देशों के लिए सबसे बड़ा है, ख़ासतौर पर उनके वंचित समुदायों के लिए। घर के भीतर के वायु प्रदूषण से दूसरी जगहों की तुलना में निम्न एच.डी.आई. वाले देशों में मरने वालों की संख्या 11 गुना अधिक है। निम्न, मध्यम तथा उच्च एच.डी.आई. वाले देशों के सुविधाहीन समूह के लोगों पर बाहरी वायु प्रदूषण का दोहरा ख़तरा होता है–एक तो इस प्रदूषण से उनका साबका अधिक पड़ता है और दूसरे, इसके प्रति उनकी अरक्षितता अधिक होती है। निम्न एच.डी.आई. वाले देशों में प्रति दस में से छह से अधिक लोगों को परिष्कृत पानी नहीं मिलता जबकि हर दस में से चार के पास स्वच्छ शौचालय नहीं हैं, जिसकी वजह से रोग और कुपोषण, दोनों होते हैं। मलेरिया, डेंगू बुखार जैसी लाक्षणिक बीमारियों के प्रसार तथा फसल उत्पादन में गिरावट के ज़रिये जलवायु परिवर्तन इन विषमताओं को और बद्तर करने का ख़तरा पैदा करता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के पास उपलब्ध 'बीमारियों का भूमंडलीय बोझ' सम्बन्धी आँकड़े पर्यावरणीय कारकों के कुप्रभाव पर कुछ चौंकाने वाले नतीजे प्रस्तुत करते हैं। इसमें यह शामिल है कि अशुद्ध पेयजल, अपर्याप्त सैनिटेशन और निजी साफ़-सफ़ाई (hygiene) में कमी दुनिया भर में रोगों के 10 सर्वप्रमुख कारणों में से हैं। हर वर्ष पर्यावरण से सम्बन्धित रोगों से, जिनमें श्वास सम्बन्धी तीक्ष्ण संक्रमण और डायरिया शामिल हैं, पाँच साल से कम उम्र के कम से कम 30 लाख बच्चे मौत के मुँह में समा जाते हैं। यह संख्या आस्ट्रिया, बेल्जियम, नीदरलैंड, पुर्तगाल और स्विट्ज़रलैंड में पाँच साल से कम उम्र के बच्चों की सम्मिलित कुल संख्या से भी अधिक है।

पर्यावरणीय क्षरण और जलवायु परिवर्तन भौतिक और सामाजिक पर्यावरण, ज्ञान, परिसंपत्तियों और व्यवहारों को भी प्रभावित करते हैं। वंचना के आयाम आपस में मिलकर प्रतिकूल प्रभावों को और अधिक बढ़ा सकते हैं–उदाहरण के लिए स्वास्थ्य सम्बन्धी जोख़िम वहाँ सबसे अधिक हैं, जहाँ पानी और साफ़-सफ़ाई, जिनकी वंचनाएँ अक्सर एक साथ उपस्थित होती हैं, अपर्याप्त हैं। उन दस देशों में से, जहाँ पर्यावरणीय आपदाओं से सबसे अधिक मौतें होती हैं, नाइजर, माली और अंगोला सहित छह देश वे हैं, जो दस सबसे अधिक एम.पी.आई. वाले देशों में भी शामिल हैं (रेखांकन 7)।

वंचित बच्चों, ख़ासतौर पर लड़कियों की शैक्षिक प्रगति में बाधाएँ

दुनिया के तमाम हिस्सों में लगभग सार्वभौमिक प्राथमिक स्कूल पंजीयन के बावजूद अब भी इसमें कमियाँ हैं। निम्न एच.डी.आई. वाले देशों में प्राथमिक स्कूल की उम्र वाले हर दस में से लगभग पाँच बच्चे प्राथमिक शाला में पंजीकृत भी नहीं होते और विविध प्रकार की बाधाएँ, जिनमें कुछ पर्यावरणीय भी होती हैं, नामांकित बच्चों को भी झेलनी पड़ती हैं। उदाहरण के लिए, बिजली की कमी के प्रत्यक्ष और परोक्ष (indirect), दोनों तरह के प्रभाव होते हैं। बिजली की उपलब्धता से बेहतर रौशनी उपलब्ध हो सकती है, जिससे पढ़ने के लिए मिलने वाला समय बढ़ जाता है और आधुनिक स्टोवों के उपयोग से जलाऊ लकड़ी तथा पानी इकट्ठा करने का समय बच जाता है। नहीं तो, ये दो वे गतिविधियाँ हैं जो शैक्षणिक प्रगति को धीमा करती हैं और पाठशाला पंजीयन में कमी लाती हैं। लडकियों पर इनका अक्सर अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि संसाधन जुटाने और स्कूल जाने, दोनों काम एक साथ करने की संभावना उनके लिए ही अधिक होती है। साफ़ पानी और परिष्कृत साफ़-सफ़ाई की उपलब्धता भी लड़कियों के लिए ही ख़ास तौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उन्हें बेहतर स्वास्थ्य, समय की बचत और एकांत उपलब्ध हो पाता है।

अन्य प्रभाव

घरेलू पर्यावरणीय वंचनाएँ व्यापक पर्यावरणीय दबावों के साथ मिलकर, व्यापक सन्दर्भों में, लोगों की पसंदों को संकुचित कर सकती हैं और प्राकृतिक संसाधनों से आजीविका कमा पाना और मुश्किल कर सकती हैंः लोगों को उतना ही प्रतिफल पाने के लिए अधिक काम करना पड़ता है या यहाँ तक कि इस पर्यावरणीय क्षरण से छुटकारा पाने के लिए उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता है।

संसाधनों पर आधारित आजीविकाएँ, ख़ासतौर पर वे, जहाँ परिवारों के पास आधुनिक रसोई ईंधन और साफ़ पानी नहीं होता, काफ़ी समय बर्बाद करने वाली होती हैं। और समय-उपयोग के सर्वे वह झरोखा खोलते हैं जिससे इससे जुड़ी लैंगिक असमानताएँ देखी जा सकती हैं। आमतौर पर औरतें पुरुषों की तुलना में लकड़ी और पानी इकट्ठा करके लाने में कहीं अधिक समय ख़र्च करती हैं और लड़कियाँ लड़कों की तुलना में कहीं अधिक, जिससे उनके (स्त्री समुदाय के) अधिक प्रतिफल वाली गतिविधियों में हिस्सेदारी बाधित होती है।

जैसा कि 2009 की एच.डी.आर. में तर्क दिया गया था, गतिशीलता –यानी लोगों को अपनी पसंद की जगह जाकर रहने की अनुमति–लोगों की स्वतंत्रता के विस्तार और बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन क़ानूनी बाधाएँ प्रवास (migration) को जोख़िमों भरा बना देती हैं। यह अनुमान लगा पाना कि पर्यावरणीय दबावों से बचने के लिए कितने लोग एक से दूसरी जगह गये, मुश्किल होता है क्योंकि दूसरे कारक भी इसमें अपनी भूमिका निभाते हैं; ख़ासतौर पर ग़रीबी। बावजूद इसके, कुछ आकलन बहुत ऊँचे हैं।

पर्यावरणीय दबाव संघर्षों की बढ़ी हुई संभावनाओं से भी जुड़ा हुआ है। हालाँकि, यह कड़ी प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन यह वृहत्तर राजनैतिक अर्थव्यवस्था तथा उन सन्दर्भ-गत (contextual) कारकों से प्रभावित होती है जो व्यक्तियों, समुदायों और समाज को पर्यावरणीय क्षरण के प्रभावों के प्रति अरक्षित बनाते हैं।

चरम मौसमी घटनाओं के असमानताकारी (disequalizing) प्रभाव

दीर्घकालिक घातक प्रभावों के साथ-साथ पर्यावरणीय क्षरण तीखे ख़तरों की संभावना को बढ़ा सकता है और इसके प्रभाव समानता घटाने वाले हो सकते हैं। हमारी विवेचना बताती है कि चरम मौसमी घटनाओं से प्रभावित लोगों की संख्या में 10 फ़ीसदी की बढ़ोत्तरी एक देश की एच.डी.आई. को 2 प्रतिशत घटा देती है, इसका आमदनियों पर और मध्यम एच.डी.आई. देशों में व्यापक प्रभाव पड़ता है।

चरम मौसमी घटनाओं से प्रभावित लोगों की संख्या में 10 फ़ीसदी की बढ़ोत्तरी एक देश की एच.डी.आई. को 2 प्रतिशत घटा देती है, इसका आमदनियों पर और मध्यम एच.डी.आई. देशों में व्यापक प्रभाव पड़ता है

और इसका बोझ सभी पर बराबर नहीं पड़ताः बाढ़, तूफ़ान और भूस्खलन से चोटों और मौत का ख़तरा बच्चों, औरतों और बूढ़े लोगों, ख़ासतौर से ग़रीबों पर अधिक होता है। प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव की यह तीखी लैंगिक असमानता इस ओर इशारा करती है कि जोख़िमों की ये असमानताएँ–और साथ ही संसाधनों तक पहुँच, क्षमताओं तथा अवसरों की असमानताएँ–एक व्यवस्था के रूप में कुछ औरतों को और अधिक असुरक्षित बनाकर उनकी वंचितता को बढ़ाती हैं।

मौसमी आघातों से स्कूल प्रभावित होते हैं और कुपोषण की स्थितियाँ बनती हैं, और इनके दूरगामी प्रभावों से बच्चे बेहिसाब कष्ट पाते हैं, उनकी संभावनाएँ कुंठित होती हैं। कई विकासशील देशों के साक्ष्य दिखाते हैं कि कैसे आय पर होने वाले अस्थायी आघात परिवारों को अपने बच्चों के स्कूल छुड़ाने का कारण बन सकते हैं। मोटे तौर पर, आघात का प्रकार, सामाजिक-आर्थिक दशा, सामाजिक पूँजी और अनौपचारिक समर्थन, और, बचाव तथा पुनर्निर्माण के प्रयासों में बरती गयी समता तथा कुशलता आदि ऐसे अहम कारक हैं, जो परिवारों पर होने वाले प्रतिकूल आघातों और उन्हें बर्दाश्त करने की उनकी क्षमता का निर्धारण करते हैं।

सशक्तीकरण–प्रजनन सम्बन्धी चयन और राजनीतिक असंतुलन

लैंगिक भूमिकाओं में रूपांतरण और सशक्तीकरण ने मानव विकास को बढ़ा कर कई देशों और समूहों को पर्यावरणीय संवहनीयता तथा असमता को सुधारने में समर्थ किया है।

लैंगिक असमानता

हमारा लैंगिक असमानता सूचकांक (Gender

Inequality Index, जी.आई.आई.), जिसे इस साल 145 देशों के आँकड़ों से संपुष्ट किया गया है, प्रदर्शित करता है कि किस तरह प्रजननीय स्वास्थ्य सम्बन्धी बाधाएँ लैंगिक असमानता में योगदान देती हैं। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि वे देश, जहाँ सभी जगह प्रजनन पर प्रभावी नियंत्रण है, औरतों की कम सन्तानें हैं, वहाँ माँताओं और बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर है और ग्रीन हॉउस गैसों का उत्सर्जन कम है। क्यूबा, मॉरिशस, थाईलैंड और ट्यूनीशिया इसके उदाहरण हैं, जहाँ प्रजननीय स्वास्थ्य सुविधाएँ और गर्भ निरोधक आसानी से उपलब्ध हैं और वहाँ प्रति महिला प्रजनन दर दो बच्चों से भी कम है। परन्तु दुनिया भर में पर्याप्त आवश्यकताएँ अब भी बनी हुई हैं और साक्ष्य सुझाते हैं कि यदि सभी औरतें प्रजननीय चयन की आज़ादी का प्रयोग कर पातीं तो जनसंख्या वृद्धि इतनी कम हो जाती कि ग्रीन हॉउस गैसों का उत्सर्जन वर्तमान स्तर से नीचे आ जाता। अगर 2050 तक परिवार नियोजन में रह गयी कमी पूरी कर दी जाय तो इससे दुनिया में कार्बन उत्सर्जन आज की तुलना में 17 प्रतिशत कम हो जायेगा।

अगर 2050 तक परिवार नियोजन में रह गयी कमी पूरी कर दी जाय तो इससे दुनिया में कार्बन उत्सर्जन आज की तुलना में 17 प्रतिशत कम हो जायेगा

इस बात को रेखांकित करते हुए कि औरतें पूरी दुनिया में, ख़ासतौर पर सब-सहारा देशों में और साथ-साथ दक्षिण एशिया और अरब राज्यों में पुरुषों से पीछे रह गयी हैं, जी.आई.आई. राजनैतिक निर्णय-प्रक्रिया में औरतों की भागीदारी पर भी ध्यान केंद्रित करता है। इसका संवहनीयता और समता पर महत्वपूर्ण असर पड़ता है। और चूँकि संसाधन जुटाने का सर्वाधिक बोझ अक्सर औरतें ही अपने कन्धों पर ही उठाती हैं और उन पर घरेलू वायु प्रदूषण का ख़तरा सबसे ज़्यादा है, इसलिए वे ही प्राकृतिक संसाधनों सम्बन्धी निर्णयों का असर भी पुरुषों से अधिक झेलती हैं। हालिया अध्ययन बताते हैं कि न केवल औरतों की भागीदारी महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भी अहम है कि वे किस तरह तथा कितनी भागीदारी करती हैं। और चूँकि औरतें बहुधा पर्यावरण के प्रति अधिक चिंता प्रदर्शित करती हैं, पर्यावरण समर्थक नीतियों का समर्थन करती हैं और पर्यावरण समर्थक नेताओं को वोट देती हैं, महिलाओं की राजनीति और ग़ैर-सरकारी संगठनों में बड़ी भूमिका पर्यावरणीय लाभ में फलित हो सकती है और इसके सभी सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों पर अनेकानेक प्रभाव हो सकते हैं।

ये तर्क कोई नये नहीं हैं, लेकिन ये महिलाओं की प्रभावी स्वतंत्रता के विस्तार के महत्व को पुनर्स्थापित करते हैं। इसलिए, निर्णय लेने के मामलों में महिलाओं की भागीदारी का अंतर्भूत महत्व तो है ही, पर्यावरणीय क्षरण को रोकने तथा समता बढ़ाने में भी बेहद महत्व है।

सत्ता सम्बन्धी विषमताएँ

जैसा कि 2010 की एच.डी.आर. में तर्क दिया गया था, सशक्तीकरण के कई आयाम होते हैं—राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र के औपचारिक व प्रक्रिया सम्बन्धी तथा स्थानीय स्तर पर सहभागी प्रक्रियाओं सम्बन्धी। यह देखने में आया है कि राष्ट्रीय और उप राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक सशक्तीकरण पर्यावरणीय संवहनीयता को बेहतर बनाता है। सन्दर्भ व परिस्थिति की महत्ता तो है ही, लेकिन अध्ययन बताते हैं कि आमतौर पर लोकतांत्रिक देश मतदाताओं के प्रति अधिक जवाबदेह हैं तथा नागरिक अधिकारों की हिमायती होने की उनकी संभावना अधिक होती है। बहरहाल, हर जगह एक अहम चुनौती यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में भी वे ही लोग अक्सर पर्यावरणीय क्षरण से दुष्प्रभावित होते हैं जो ग़रीब हैं, सशक्तीकरण के सबसे निचले पायदान पर हैं—और इसीलिए नीतियाँ बनाने की प्राथमिकताओं में उनके हित और ज़रूरतें प्रतिबिंबित नहीं होतीं।

इस बात के साक्ष्य बढ़ रहे हैं कि तमाम देशों और विशेष परिस्थितियों में राजनीतिक संस्थाओं की मध्यस्थता से उपजी सत्ता सम्बन्धी विषमताएँ पर्यावरणीय नतीजों को प्रभावित करती हैं। इसका अर्थ यह है कि ग़रीब और अन्य सुविधाहीन समूह पर्यावरणीय क्षरण के प्रभावों का बे-हिसाब ख़ामियाज़ा भुगतते हैं। इस रिपोर्ट के लिए लगभग सौ देशों के आँकड़ों के आधार पर तैयार हुए विश्लेषण से इसकी पुष्टि होती है कि सत्ता के बँटवारे में अधिकाधिक समता का सीधा रिश्ता बेहतर पर्यावरणीय परिणामों से जुड़ा है। और इसमें पानी की बेहतर सुलभता, कम भू क्षरण और घरेलू तथा बाहरी वायु प्रदूषण तथा प्रदूषित जल से कम मौतों का होना शामिल है। इससे सकारात्मक संगतियों (positive synergies) के लिए बेहतर गुंजाइश का संकेत साफ़ तौर पर मिलता है।

सकारात्मक संगतियाँ—पर्यावरण, समता और मानव विकास की कारगर रणनीतियाँ

रिपोर्ट में विस्तार से बताई गयीं चुनौतियों का सामना करने के लिए विभिन्न सरकारों, नागर समाज, निजी क्षेत्र के सरोकारियों (stakeholders) और विकास कार्यों में सक्रिय साझेदारों ने ऐसी पद्धतियाँ निर्मित की हैं जो पर्यावरणीय संवहनीयता और समता को एकीकृत कर मानव विकास को प्रोत्साहित करती हैं— सभी के लिए लाभदायी (win-win-win) रणनीतियाँ। प्रभावी समाधानों को सन्दर्भों, परिस्थितियों के सापेक्ष ही होना चाहिए। बावजूद इसके, ऐसे स्थानीय तथा राष्ट्रीय अनुभवों पर विचार करना ज़रूरी है जो संभावनायुक्त हैं, और ऐसे सिद्धांतों की पहचान की जाय जो सभी सन्दर्भों पर सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं। स्थानीय स्तर पर हम समावेशी संस्थाओं पर ज़ोर देते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर सफल नवाचारों और नीतिगत सुधारों को बढ़ाने पर।

नीतिगत एजेंडा काफ़ी विस्तृत है। यह रिपोर्ट इसके प्रति पूरा न्याय नहीं कर सकती—लेकिन इसका योगदान सभी के लिए लाभदायी उन रणनीतियों को पहचानने में है जो

हमारी सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने में सफल हैं। ये वे रणनीतियाँ हैं जो उन पद्धतियों, जो पर्यावरण, समता और मानव विकास के लिए सहायक हैं, के लिए किये जाने वाले व्यावहारिक समझौतों (trade-offs) का समुचित प्रबन्धन करती हैं या फिर उन समझौतों से बचने का मार्ग दिखाती हैं। बहस तथा ज़मीनी कार्यवाहियों को प्रेरित करने के लिए हमने यहाँ संभावित समझौतों से पार पाने वाली रणनीतियों को प्रदर्शित करने वाले, और इसकी पहचान कराने वाले स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत किये हैं कि सकारात्मक संगतियाँ व्यावहारिक धरातल पर कैसे काम करती हैं। यहाँ हम आधुनिक ऊर्जा का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं।

आधुनिक ऊर्जा की सुलभता

ऊर्जा की मानव विकास में केन्द्रीय भूमिका है, फिर भी दुनिया भर में क़रीब 1.5 अरब लोगों, यानी हर पाँच में से एक से भी अधिक, के पास बिजली नहीं है। बहुआयामी-निर्धनों के लिए यह वंचना और भी अधिक है—हर तीन में से एक के पास बिजली उपलब्ध नहीं है।

क्या विद्युत उपलब्धता और कार्बन उत्सर्जन बढ़ाने के बीच किसी व्यावहारिक समझौते की गुंजाइश है? ज़रूरी नहीं कि हो ही। हमारा तर्क है कि दोनों के बीच का सम्बन्ध ग़लत तरीके से परिभाषित किया गया है। ऊर्जा की सुलभता बढ़ाने की तमाम ऐसी संभावनाएँ हैं जिनकी कोई भारी पर्यावरणीय क़ीमत नहीं होगी।

- विकेंद्रीकृत, ऑफ़-ग्रिड (off-grid) विकल्प ग़रीब परिवारों को ऊर्जा सम्बन्धी सेवाएँ उपलब्ध कराने में तकनीकी रूप से व्यवहार्य (feasible) हैं और जलवायु पर अति न्यून प्रभाव के साथ इन्हें वित्तपोषित किया जा सकता है।
- सभी लोगों को यदि आधुनिक ऊर्जा सेवाएँ उपलब्ध करा दी जाएँ तो, एक अनुमान के अनुसार, कार्बन डाई ऑक्साइड का उत्सर्जन केवल 0.8% बढ़ेगा—यदि पहले से ही घोषित नीतिगत वचनबद्धताओं को ध्यान रखें।

वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति 2010 में एक अनिवर्ती बिन्दु पर पहुँच गयी, जहाँ अक्षय ऊर्जा (renewables) वैश्विक ऊर्जा क्षमता की 25% हो गयी और इससे वैश्विक विद्युत उत्पादन के 18% से अधिक की आपूर्ति की जाने लगी। चुनौती यह है कि उपलब्धता को उस स्तर तक और इस गति से बढ़ाया जाय कि यह ग़रीब औरतों तथा पुरुषों के जीवन को आज तथा भविष्य के लिए बेहतर बनाये।

पर्यावरणीय क्षरण की रोकथाम

पर्यावरणीय क्षरण की रोकथाम के व्यापक तरीकों की सूची में प्रजनन सम्बन्धी चयन के अधिकार के विस्तार से लेकर सामुदायिक वन प्रबंधन को प्रोत्साहित करना और आपदा से निबटने के लिए लोचदार पहलें शामिल हैं। प्रजनन सम्बन्धी अधिकार, जिसमें प्रजननीय स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता शामिल है, महिलाओं के सशक्तीकरण की शर्त हैं और ये पर्यावरणीय क्षरण को रोक सकते हैं। इस दिशा में महत्वपूर्ण सुधार सम्भव हैं। कई उदाहरण इस काम में सामुदायिक भागीदारी के महत्व को और वर्तमान में उपलब्ध स्वास्थ्य अवसंरचनाओं को बहुत थोड़ी सी अतिरिक्त लागत के साथ प्रजननीय स्वास्थ्य सेवाएँ बेहतर करने के तथ्य को सिद्ध करते हैं। बांग्लादेश का उदाहरण लें, जहाँ प्रजनन दर 1975 के 6.6 जन्म प्रति महिला से घटकर 2009 में 2.4 हो गयी। सरकार ने गर्भ निरोधकों पर छूट दी, उनकी उपलब्धता बढ़ाई तथा पुरुष व महिला वैचारिक नेताओं, जिनमें धार्मिक नेता, शिक्षक और ग़ैर-सरकारी संगठन शामिल थे, के साथ विचार-विमर्श कर इससे जुड़ी सामाजिक कसौटियों को प्रभावित किया।

सामुदायिक वन प्रबंधन स्थानीय पर्यावरणीय क्षरण का समाधान कर सकता है और कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकता है, लेकिन अनुभव यह भी बताते हैं कि इसमें पहले से ही हाशिये पर खड़े लोगों के और अधिक वंचित हो जाने के भी ख़तरे हैं। इन ख़तरों से बचने के लिए हमने वन प्रबंधन के कार्यक्रम बनाने में तथा उसके क्रियान्वयन में व्यापक भागीदारी के, ख़ासतौर पर महिलाओं की भागीदारी के महत्व को रेखांकित किया है, और इस पर भी ज़ोर दिया है कि यह सुनिश्चित किया जाय कि ग़रीब समूह तथा वन संसाधनों पर निर्भर रहने वाले लोगों के हालात बद्तर न हों।

नयी सूझ वाली सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तथा समतापरक व आपदाओं से निपटने की लोचदार कार्यप्रणालियों के माध्यम से आपदाओं के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के आशाजनक रास्ते भी उभर रहे हैं। आपदाओं से निपटने में समुदाय आधारित जोख़िम-आकलन के तरीके तथा पुनर्निर्मित संपत्ति का अधिक प्रगतिशील व समतापरक वितरण शामिल हैं। अनुभवों ने जोख़िमों को घटाने के विकेंद्रीकृत मॉडलों की ओर झुकाव को प्रेरित किया है। ऐसे प्रयास योजना निर्माण तथा निर्णय-प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों, ख़ासतौर पर औरतों की भागीदारी पर बल देकर उनका सशक्तीकरण कर सकते हैं। समुदाय इस तरह से पुनर्गठित हो सकते हैं कि वे वर्तमान की असमानताओं का निवारण स्वयं कर सकें।

> ऊर्जा की उपलब्धता बढ़ाने की तमाम ऐसी संभावनाएँ हैं जिससे कोई भारी पर्यावरणीय क्षति नहीं होगी

अपने विकास माडल पर पुनर्विचार—बदलाव के उत्प्रेरक

लोगों, समूहों और देशों के बीच की व्यापक असमानताएँ बड़े और लगातार गहराते पर्यावरणीय ख़तरे को बढ़ाती हैं और कठिन नीतिगत चुनौतियाँ पेश करती हैं। लेकिन आशावादिता के भी पर्याप्त कारण हैं। दुनिया के कुछ हिस्सों में नवाचारी पहलों और नीतियों के चलते विकास की परिस्थितियाँ पहले के मुक़ाबले आज अधिक अनुकूल हैं। इस बहस को आगे बढ़ाना निर्भीक सोच को अपरिहार्य कर देता है, ख़ासतौर पर संवहनीय विकास पर संयुक्त

राष्ट्र के समेलन (रियो+20) की पूर्वसंध्या पर और 2015 के बाद के युग के इस उषा-काल में। यह रिपोर्ट मानव विकास को बढ़ावा देने के लिए संवहनीयता तथा समता की दृष्टियों को मिलाकर एक नया दृष्टिकोण सामने रखती है। स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर हम समता को नीतिगत तथा कार्यक्रम निर्धारण के सबसे अग्रस्थान पर लाने की ज़रूरत पर बल देते हैं, साथ ही, क़ानूनी तथा राजनीतिक क्षेत्रों में हुए बेहतर सशक्तीकरण के सम्भाव्य व्यापक प्रभावों का भी उचित दोहन किये जाने की ज़रूरत को रेखांकित करते हैं। भूमण्डलीय स्तर पर हम भयावह होते जा रहे पर्यावरणीय ख़तरों के निवारण पर अधिक संसाधन लगाने की ज़रूरत, और वंचित देशों व समूहों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने तथा उनके बीच समता सुनिश्चित कर वित्त की सुलभता बढ़ाने की ज़रूरत को रेखांकित करते हैं।

पर्यावरणीय नीतियों के मूल्यांकन की पारंपरिक विधियाँ वितरण के मुद्दों पर अक्सर चुप्पी साध जाती हैं। यद्यपि हरित अर्थव्यवस्था की नीतियों के उद्देश्यों में समता और समावेशन (inclusion) का महत्व पहले से ही सुस्पष्ट है, हम इस एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव करते हैं

समता के सरोकारों का हरित अर्थव्यस्था की नीतियों से एकीकरण

समता के सरोकारों को पर्यावरण प्रभावित करने वाली नीतियों में सम्मिलित करना इस रिपोर्ट की एक महत्वपूर्ण विषय-वस्तु है। इस काम में पर्यावरणीय नीतियों के मूल्यांकन की पारंपरिक विधियाँ अपर्याप्त हैं। उदाहरण के लिए, वे भविष्य के उत्सर्जनों के प्रभावों को एकबारगी बेनक़ाब कर भी सकती हैं, लेकिन वितरण सम्बन्धी मुद्दों पर वे अक्सर चुप्पी साध जाती हैं। यहाँ तक कि जब विभिन्न समूहों पर प्रभाव की बात की जाती है तो आमतौर पर ध्यान लोगों की आय तक ही सीमित रह जाता है। हरित अर्थव्यवस्था की नीतियों के उद्देश्यों में समता और समावेशन (inclusion) का महत्व पहले से ही सुस्पष्ट है। हम इस एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव करते हैं।

ऐसे कई महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो नीति-निर्माण से जुड़े विश्लेषण में सरोकारियों को शामिल करके इस प्रक्रिया में समता के व्यापक मूल्यों का समावेश कर सकते हैं। विश्लेषण की इस प्रक्रिया में निम्न बिन्दुओं का ध्यान रखा जाना चाहिएः

- एम.पी.आई. सरीखी विधियों की मदद से खुशहाली के ग़ैर-आय आयामों का
- नीति के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभावों का
- प्रतिकूल रूप से प्रभावित लोगों के लिए मुआवज़े की प्रक्रियाओं का
- उन चरम मौसमी घटनाओं के जोख़िमों का, जिनके होने की आशंका भले ही बेहद कम हो, लेकिन जो अति विनाशकारी हो सकती हैं।

नीतियों के वितरणतात्मक एवं पर्यावरण सम्बन्धी प्रभावों का समय रहते विश्लेषण किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

साफ़ और सुरक्षित पर्यावरण—सुविधा नहीं, अधिकार

राष्ट्रीय संविधानों और क़ानूनों में पर्यावरणीय अधिकारों को शामिल करना प्रभावी हो सकता है, क्योंकि वह नागरिकों को ऐसे अधिकारों की रक्षा के लिए सक्षम बनाता है। कम से कम 120 देशों में ऐसे संविधान हैं जो पर्यावरणीय कसौटियों पर ध्यान देते हैं। और कई देशों में, जहाँ पर्यावरणीय अधिकार सुस्पष्ट नहीं हैं, वहाँ वे नागरिकों के निजी अधिकारों के लिए बने सामान्य संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या इस तरह करते हैं कि उसमें एक स्वस्थ पर्यावरण को पाने का मूलभूत अधिकार शामिल हो।

स्वस्थ पर्यावरण सबका समान अधिकार है— इस प्रस्थापना को संवैधानिक तौर पर स्वीकारने से समता को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि तब इसकी पहुँच केवल समर्थ लोगों तक सीमित नहीं रह जाती। और इन अधिकारों को क़ानूनी ढाँचे में मूर्त रूप देना सरकारी वरीयताओं और संसाधन आवंटन को प्रभावित कर सकता है।

एक स्वस्थ और संतुलित पर्यावरण पर समान अधिकार को क़ानूनी मान्यता देने के साथ ही इस बात की भी ज़रूरत है कि संस्थाएँ सक्षम बनें, जैसे कि निष्पक्ष और स्वतन्त्र न्यायपालिका, और सरकारों तथा निकायों से सूचना पाने का अधिकार भी शामिल हो। अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी लगातार पर्यावरणीय सूचना के अधिकार को अधिकाधिक मान्यता दे रहा है।

भागीदारी और जवाबदारी

प्रक्रियाएँ अपनाने की स्वतंत्रता मानव विकास के लिए केन्द्रीय महत्व की है और, जैसा कि पिछले वर्ष की एच.डी.आर. में चर्चा की गयी थी, इनका एक अंतर्भूत ठोस महत्व है। सत्ता में ग़ैर-बराबरी का असर पर्यावरणीय परिणामों में बड़ी असमानताओं के रूप में रूपान्तरित होता है। लेकिन इसके उलट पक्ष यह भी है कि अधिकाधिक सशक्तीकरण से समतापरक और सकारात्मक पर्यावरणीय परिणाम आ सकते हैं। लोकतंत्र महत्वपूर्ण है लेकिन इसके आगे की बात यह है कि राष्ट्रीय संस्थाओं को जवाबदेह और समावेशी होना चाहिए—ख़ासतौर पर महिलाओं सहित प्रभावित समूहों के संदर्भ में—जिससे नागर समाज को सशक्त कर आम जनता की सूचना तक पहुँच को बढ़ाया जा सके।

भागीदारी की एक शर्त है विचार-विमर्श की प्रक्रियाओं का खुला, पारदर्शी और समावेशी होना—लेकिन व्यवहार में देखें, तो प्रभावी भागीदारी की राह में अभी भी रोड़े हैं। आशाजनक परिवर्तन के बावजूद, कुछ पारंपरिक रूप से बहिष्कृत समूहों, जैसे आदि-निवासियों, को मज़बूती देने के लिए प्रयास सघन करने की ज़रूरत है ताकि एक सक्रिय भूमिका अदा करने की उनकी संभावनाएँ बढ़ सकें। और लगातार बढ़ते साक्ष्य महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने की महत्ता इंगित करते हैं, क्योंकि यह अपने आप में तो महत्वपूर्ण है ही, यह अधिक संवहनीय परिणामों से जुड़ा है।

जहाँ सरकारें आम जनता के सरोकारों के प्रति

संवेदनशील हैं, वहाँ परिवर्तन अधिक सम्भाव्य है। एक ऐसा वातावरण जहाँ नागर-समाज सबल व सक्रिय है, वहाँ स्थानीय, राष्ट्रीय और भूमंडलीय स्तरों पर जवाबदेही की संभावनाएँ भी पैदा होती हैं, जबकि प्रेस की स्वतंत्रता जागरूकता बढ़ाने और जन भागीदारी सुगम बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

निवेशों का वित्तीयन—हम आज कहाँ हैं ?

संवहनीयता सम्बन्धी बहसें लागतों और वित्तीयन के बड़े प्रश्न खड़े करती हैं—जैसे, कौन किसका वित्तपोषण करे और कैसे? समता के सिद्धांत ग़रीब देशों को बढ़े पैमाने पर संसाधन स्थानांतरित करने की पैरवी करते हैं ताकि वे जल एवं ऊर्जा की समतापरक उपलब्धता का लक्ष्य पा सकें और साथ ही, जलवायु परिवर्तन से अनुकूलन और इसके दुष्प्रभावों के शमन, दोनों का वित्तीय भार उठा सकें।

हमारी वित्तीयन सम्बन्धी विवेचना से चार महत्वपूर्ण सन्देश उभरते हैं:

- निवेश आवश्यकताएँ विशाल हैं लेकिन वे दूसरे क्षेत्रों, जैसे सेना, पर होने वाले वर्तमान ख़र्चे से ज़्यादा नहीं हैं। ऊर्जा के आधुनिक स्रोतों की सार्वभौमिक उपलब्धता प्राप्त करने के लिए आवश्यक अनुमानित वार्षिक निवेश जीवाश्म ईंधनों को दी जाने वाली वार्षिक रियायतों (subsidies) के आठवें हिस्से से भी कम है।
- सार्वजनिक क्षेत्र की वचनबद्धताएँ ज़रूरी हैं (कुछ दाताओं की उदारता अलग से दिखाई देती है), और निजी क्षेत्र वित्त का एक बड़ा और महत्वपूर्ण स्रोत है। सार्वजनिक प्रयास निजी निवेश के उत्प्रेरक हो सकते हैं—सार्वजनिक कोष में बढ़ोत्तरी के महत्व पर बल देते हुए और सकारात्मक निवेश-वातावरण तथा स्थानीय क्षमता का समर्थन कर।
- आँकड़ों का अभाव निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा पर्यावरणीय संवहन पर किये गये व्यय की निगरानी मुश्किल बना देता है। उपलब्ध आँकड़े केवल आधिकारिक स्तर पर विकास के लिए दी गयी सहायता के परीक्षण की अनुमति देते हैं।
- वित्तपोषण की प्रक्रियागत संरचना जटिल और कई हिस्सों में बँटी होती है, जिससे इसका प्रभाव कम हो जाता है तथा तत्सम्बन्धी ख़र्च की निगरानी मुश्किल हो जाती है। पेरिस और अक्रा (Accra) में आर्थिक मदद की प्रभाविता को बढ़ाने के लिए पूर्व में तय की गयी प्रतिबद्धताओं से बहुत कुछ सीखा जा सकता है।

हालाँकि, आवश्यकताओं, वचनबद्धताओं और भुगतान से सम्बन्धित साक्ष्य अपूर्ण हैं और उनके परिमाण अनिश्चित हैं, तस्वीर बिल्कुल साफ़ है। विकास के लिए आधिकारिक वित्तीय सहायता के मद में व्यय और जलवायु परिवर्तन, निम्न कार्बन वाली ऊर्जा और जल तथा साफ़-सफ़ाई की समस्याओं से निपटने के लिए वांछित निवेश में बड़ा अंतर है—ये अंतर वचनबद्धताओं और निवेश आवश्यकताओं के बीच के अंतर से भी अधिक है (रेखांकन 8)। निम्न-कार्बन ऊर्जा स्रोतों पर व्यय न्यूनतम आवश्यकताओं के अनुमानों (lower bound estimate) का भी लगभग 1.6% ही है, जबकि जलवायु परिवर्तन से अनुकूलन और उसके दुष्प्रभाव के शमन पर व्यय अनुमानित न्यूनतम आवश्यकताओं का 11% है। पानी तथा साफ़-सफ़ाई के लिए वांछित धनराशि तुलनात्मक रूप से काफ़ी कम है और आधिकारिक सहायता की वचनबद्धताएँ अनुमानित लागत के काफ़ी क़रीब हैं।

वित्तपोषण के अंतर को पाटना: मुद्रा विनिमय कर—शानदार विचार से व्यावहारिक नीति तक

इस रिपोर्ट में प्रलेखित चुनौतियों और वंचनाओं से निपटने के लिए उपलब्ध संसाधनों के वित्तपोषण में अंतराल नये अवसरों का लाभ उठाकर काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा विनिमय कर है। वर्ष 1994 के एच.डी.आर. में प्रस्तावित यह विचार अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों द्वारा एक व्यावहारिक नीतिगत विकल्प के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। हालिया वित्तीय संकट ने इसकी प्रासंगिकता को रेखांकित करते हुए इस प्रस्ताव में रूचि को पुनर्जीवित किया है।

वर्तमान में विदेश मुद्रा विनिमय के निपटारे की प्रक्रियाएँ अधिक व्यवस्थित, केंद्रीकृत और मानकीकृत हैं, इसलिए इस कर को लागू किये जाने की व्यवहार्यता नये सिरे से रेखांकित की जानी चाहिए। इसे उच्च स्तर का अनुमोदन प्राप्त है, जिसमें नवाचारी वित्तीयन पर बना प्रमुख समूह (Leading Group on Innovating Financing) शामिल है। इस समूह में कोई 63 देश हैं, जिनमें चीन, फ्रांस, जर्मनी, जापान और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन वित्तीयन की उच्च स्तरीय सलाहकार समिति ने हाल ही में यह प्रस्ताव दिया कि इस तरह के कर से प्राप्त राशि का 25-50% विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा निवारण के मद में दिया जाय।

हमारी अद्यतन विवेचना बताती है कि एक अत्यंत निम्न दर (0.005%) पर और बिना किसी अतिरिक्त प्रशासनिक लागत के मुद्रा विनिमय कर लगभग $40 अरब की अतिरिक्त आय अर्जित करा सकता है। अंतरराष्ट्रीय बहसों में जिस अतिरिक्त वित्तपोषण की ज़रूरत पर बल दिया गया है, उसे पूरा कर सकने वाले (इसके अलावा) दूसरे विकल्प अधिक नहीं हैं।

एक व्यापक वित्तीय विनिमय कर बड़ी आय संभावनाओं का भी वादा करता है। अधिकांश जी-20 देशों ने पहले ही वित्तीय विनिमय कर लागू कर दिया है, और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ़.) ने एक व्यापक कर की प्रशासनिक व्यवहार्यता की पुष्टि की है। इस करके एक संस्करण में घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय विनिमयों पर 0.05% की लेवी से, एक अनुमान के अनुसार, $6 से 7 खरब की धनराशि अर्जित की जा सकती है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार

एक अत्यंत निम्न दर पर और बिना किसी अतिरिक्त प्रशासनिक लागत के मुद्रा विनिमय कर लगभग 40 अरब डॉलर की अतिरिक्त आय अर्जित करा सकता है। अंतरराष्ट्रीय बहसों में जिस अतिरिक्त वित्तपोषण की ज़रूरत पर बल दिया गया है, उसे पूरा कर सकने वाले (इसके अलावा) दूसरे विकल्प अधिक नहीं हैं

रेखांकन 8

विकास के लिए आधिकारिक सहायता अपर्याप्त है

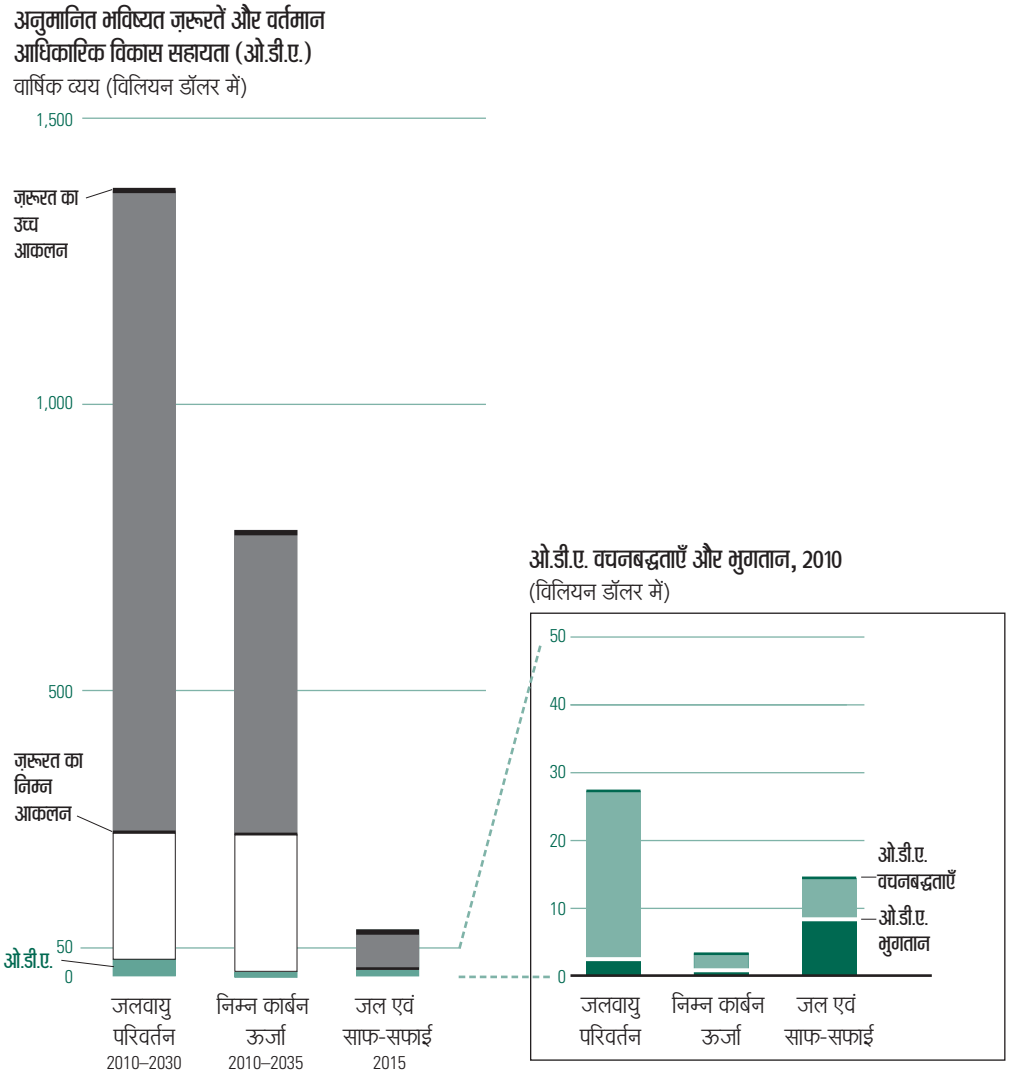

स्रोतः अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेन्सी, 2010, विश्व ऊर्जा दृष्टिकोण, पेरिसः आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन; यू.एन. वाटर, 2010, ग्लोबल एनुअल असेसमेंट ऑफ़ सैनिटेशन एण्ड ड्रिंकिंग वाटरः टार्गेटिंग रिसोर्सेज़ फ़ॉर बैटर रिज़ल्ट्स, जिनीवाःवर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज़ेशन; संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक विकास विभाग, 2010, प्रमोटिंग डेवलपमेंट, सेविंग द प्लैनेट, न्यूयॉर्कः यूनाइटेड नेशन्स, और अनुदान गतिविधियों पर ओ.ई.सी.डी. के विकास सम्बन्धी आँकड़ेः सी.आर.एस. ऑनलाइन।

(Special Drawing Rights) के अतिरेक (surplus) के एक हिस्से के मौद्रीकरण ने भी ध्यान आकर्षित किया है। इससे योगदानकर्ता देशों से बहुत कम या शून्य बजटीय लागत पर $75 अरब की धनराशि जुटाई जा सकती है। एस.डी.आर. में एक अतिरिक्त आकर्षण यह है कि वे मुद्रा पुनर्संतुलन के साधन हैं, अपने कोष (reserves) को विविधता प्रदान करना चाहने वाली उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं से इनकी माँग आने की उम्मीद है।

बेहतर समता और भागीदारी के लिए सुधार

नीति-निर्माताओं, वार्ताकारों तथा निर्णय-कर्ताओं और पर्यावरणीय क्षरण से सर्वाधिक अरक्षित नागरिकों के बीच की दूरियाँ घटाने के लिए वैश्विक पर्यावरणीय अधिशासन में व्याप्त जवाबदेही-अंतराल को पाटने की ज़रूरत है। यद्यपि जवाबदेही अकेले इस चुनौती का सामना नहीं कर सकती, लेकिन यह सामजिक और पर्यावरणीय दृष्टि से प्रभावी एक ऐसी वैश्विक अधिशासन प्रणाली के निर्माण की मूलभूत अनिवार्यता है, जो लोगों की ज़रूरतें पूरी कर सके।

हम अपील करते हैं कि पर्यावरणीय क्षरण का मुक़ाबला करने वाले प्रयासों को वित्त उपलब्ध कराने में समता और भागीदारी बढ़ाने वाले क़दम उठाये जाएँ।

निजी संसाधन आवश्यक हैं। उदाहरण के लिए ऊर्जा क्षेत्र में वित्तीय प्रवाह का अधिकतम हिस्सा निजी क्षेत्र से आता है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में निजी निवेशकों की दृष्टि में तुलनात्मक रूप से अधिक जोख़िम और कम लाभ

हैं, जो इन प्रवाहों के स्वरूप को प्रभावित कर सकते हैं। अगर सुधार नहीं हुए, तो तमाम देशों के बीच वित्तीयन का बँटवारा असमान होगा तथा यह ज़ाहिरा तौर पर मौजूदा असमानताओं को और विकृत ही करेगा। इससे सार्वजनिक निवेश के प्रवाहों को समतापूर्ण बनाने तथा भविष्य में निजी निवेश को आकर्षक बनाने का महत्व स्पष्ट होता है।

इसके निहितार्थ स्पष्ट हैं–समता के सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रवाह को निर्देशित तथा प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक हैं। संस्था निर्माण के लिए सहयोग आवश्यक है ताकि विकासशील देश उपयुक्त नीतियों तथा उत्प्रेरकों (incentives) को गतिशील कर सकें। अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक वित्तीयन से सम्बद्ध अधिशासन तंत्र को भागीदारी तथा सामाजिक जवाबदेही सुनिश्चित करनी ही चाहिए।

जलवायु-परिवर्तन को धीमा करने या रोकने की कोशिशों के विस्तारण (scale up) के लिए किसी भी प्रभावी बदलाव के प्रयास को ज़रूरत होगी घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय, निजी तथा सरकारी, अनुदान तथा कर्ज़ से जुड़े संसाधनों को एकजुट करने की। समतापूर्ण उपलब्धता तथा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रवाहों के कुशल उपयोग, दोनों को सुगम बनाने के लिए यह रिपोर्ट देशों के स्तर पर जलवायु सम्बन्धी वित्त के समायोजन के लिए राष्ट्रीय साझेदारों के सशक्तीकरण की वकालत करती है। राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु कोष घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय, निजी तथा सरकारी और अनुदान तथा कर्ज़ जैसे संसाधनों के व्यावहारिक मिश्रण तथा निगरानी को सुगम बना सकते हैं। यह देश के भीतर जवाबदारी और वितरण के सकारात्मक प्रभावों को सुनिश्चित करने के लिए अति आवश्यक है।

यह रिपोर्ट इस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए देशों के स्तर पर चार पद्धति-समूहों पर बल दिये जाने को प्रस्तावित करती हैः

- *निम्न उत्सर्जन, जलवायु प्रत्यास्थ (resilient) रणनीतियाँ*– जिससे मानव विकास, समानता तथा जलवायु परिवर्तन के लक्ष्य एक ही कड़ी के हिस्से बन जाएँ।
- *निजी-सार्वजनिक भागीदारियाँ*–जिससे परिवारों तथा व्यवसायों से पूँजी को उत्प्रेरित किया जा सके।
- *जलवायु सम्बन्धी समझौतों से प्रवाहित वित्त की सुविधाएँ*–जिससे अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त प्रवाहों की समतापरक उपलब्धता कराई जा सके।
- *समन्वित कार्यान्वयन और निगरानी, रिपोर्टिंग तथा सत्यापन प्रणालियाँ*–जिससे दीर्घकालिक तथा कुशल परिणाम प्राप्त हो सकें और स्थानीय जनता के साथ-साथ भागीदारों के प्रति भी जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

अंत में, हम एक उच्च स्तरीय, वैश्विक ऊर्जा सुलभता पहल (Universal Energy Access Initiative) की अपील करते हैं जिससे देशों के स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन के लिए पैरोकारी पनपे, जागरूकता बढ़े और समर्पित प्रयास हों। इस तरह की पहल छोटे क्रमागत परिवर्तनों की बजाय एक आमूलचूल बदलाव को प्रसवित कर सकती है।

* * *

यह रिपोर्ट संवहनीयता और समता के बीच की कड़ियों पर प्रकाश डाल कर यह प्रदर्शित करती है कि मानव विकास कैसे और अधिक संवहनीय तथा समतापरक हो सकता है। यह उजागर करती है कि कैसे पर्यावरणीय क्षरण ग़रीबों तथा वंचित समूहों को दूसरों के मुकाबले अधिक नुक्सान पहुँचाता है। हम एक ऐसा नीतिगत एजेंडा प्रस्तावित करते हैं जो वर्तमान पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए समता और मानव विकास को प्रोत्साहित करने वाली रणनीतियाँ बना कर इन असंतुलनों से निपट सके। हमने इन पूरक उद्देशयों को एक साथ आगे बढ़ाने के व्यावहारिक रास्ते बताये हैं, वे रास्ते जो हमारे पर्यावरण को संरक्षित करते हुए लोगों के विकल्पों का विस्तार करते हैं।

जलवायु-परिवर्तन को धीमा करने या रोकने की कोशिशों के विस्तारण (scale up) के लिए किसी भी प्रभावी बदलाव के प्रयास को ज़रूरत होगी घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय, निजी तथा सरकारी, अनुदान तथा कर्ज़ से जुड़े संसाधनों को एकजुट करने की

2011 की एच.डी.आई. श्रेणी और श्रेणी में 2010 से 2011 में हुए उतार-चढ़ाव

अफ़ग़ानिस्तान	172		
अल्बानिया	70	↑	1
अल्जीरिया	96		
एन्डोरा	32		
अंगोला	148		
एंटीगुआ और बरबूडा	60	↑	1
अर्जेन्टीना	45	↑	1
आर्मेनिया	86		
ऑस्ट्रेलिया	2		
ऑस्ट्रिया	19		
अज़रबैजान	91		
बहामास	53		
बहरीन	42		
बांग्लादेश	146		
बारबाडोस	47		
बेलारूस	65		
बेल्जियम	18		
बेलीज़	93	↓	–1
बेनिन	167		
भूटान	141	↓	–1
प्लूरीनेशनल स्टेट ऑफ़ बोलीविया	108		
बोस्निया और हर्ज़ेगोविना	74		
बोत्स्वाना	118	↓	–1
ब्राज़ील	84	↑	1
ब्रूनेई दारस्सलाम	33		
बुल्गारिया	55	↑	1
बुर्कीना फ़ासो	181		
बुरुण्डी	185		
कम्बोडिया	139	↑	2
कैमरून	150	↑	1
कनाडा	6		
केप वर्दे	133		
सेन्ट्रल अफ़्रीकन रिपब्लिक	179		
चाड	183	↓	–1
चिली	44		
चीन	101		
कोलम्बिया	87	↑	1
कॉमोरॉस	163		
कॉन्गो	137		
कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य	187		
कोस्टारिका	69	↓	–1
आइवरी कोस्ट	170		
क्रोएशिआ	46	↓	–1
क्यूबा	51		
साइप्रस	31		
चेक गणराज्य	27		
डेनमार्क	16		
जिबूती	165	↓	–1
डोमिनिका	81	↓	–1
डोमिनिकन गणराज्य	98	↑	2
इक्वाडोर	83		
मिस्र	113	↓	–1
अल सल्वाडोर	105		
इक्वाटोरिअल गिनी	136	↓	–1
एरिट्रिआ	177		
एस्टोनिया	34		
इथियोपिया	174		
फ़िजी	100	↓	–3
फ़िनलैंड	22		
मेसाडोनिया, पूर्ववर्ती यूगोस्लाव गणराज्य	78	↓	–2
फ़्रांस	20		
गैबन	106		
गैम्बिआ	168		
जॉर्जिआ	75		
जर्मनी	9		
घाना	135	↑	1
ग्रीस	29		
ग्रेनाडा	67		
ग्वाटेमाला	131		
गिनी	178		
गिनी-बिसाउ	176		
गयाना	117	↑	2
हैती	158	↑	1
होण्डुरास	121	↓	–1
हांगकांग, चीन (एस.ए.आर.)	13	↑	1
हंगरी	38		
आइसलैंड	14	↓	–1
भारत	134		
इण्डोनेशिया	124	↑	1
ईरान इस्लामिक गणराज्य	88	↓	–1
इराक	132		
आयरलैंड	7		
इस्राइल	17		
इटली	24		
जमैका	79	↓	–1
जापान	12		
जॉर्डन	95	↓	–1
कज़ाकिस्तान	68	↑	1
कीन्या	143	↑	1
किरिबाती	122		
कोरिया गणराज्य	15		
कुवैत	63	↓	–1
किर्गिस्तान	126		
लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक	138	↑	1
लात्विया	43		
लेबनान	71	↓	–1
लेसोथो	160		
लाइबेरिया	182	↑	1
लीबिया	64	↓	–10
लिक्टेन्सटाइन	8		
लिथुआनिया	40	↑	1
लक्ज़मबर्ग	25		
मैडागास्कर	151	↓	–2
मलावी	171		
मलेशिया	61	↑	3
माल्दीव	109		
माली	175		
माल्टा	36		
मॉरितानिया	159	↓	–1
मॉरिशस	77		
मैक्सिको	57		
फेडरेटेड स्टेट ऑफ़ माइक्रोनेशिया	116		
माल्डोवा गणराज्य	111		
मंगोलिया	110		
मॉन्टीनेग्रो	54	↑	1
मोरक्को	130		
मोज़ाम्बीक	184		
म्याँमार	149	↑	1
नामीबिआ	120	↑	1
नेपाल	157	↓	–1
नीदरलैंड	3		
न्यूज़ीलैंड	5		
निकारागुआ	129		
नाइजर	186		
नाइजीरिया	156	↑	1
नॉर्वे	1		
अधिकृत फलस्तीनी क्षेत्र	114		
ओमान	89		
पाकिस्तान	145		
पलाऊ	49		
पनामा	58	↑	1
पापुआ न्यू गिनी	153	↓	–1
पराग्वे	107		
पेरू	80	↑	1
फ़िलीपीन्स	112	↑	1
पोलैण्ड	39		
पुर्तगाल	41	↓	–1
कतर	37		
रोमानिआ	50		
रशियन फ़ेडरेशन	66		
रवाण्डा	166		
सेन्ट किट्स एवं नेविस	72		
सेन्ट लूसिआ	82		
सेन्ट विन्सेन्ट एवं ग्रेनाडाइन्स	85	↓	–1
समोआ	99		
साओ टोमे और प्रिन्साइप	144	↓	–1
सऊदी अरब	56	↑	2
सेनेगल	155		
सर्बिआ	59	↑	1
सेशेल्स	52		
सिएरे लिओन	180		
सिंगापुर	26		
स्लोवाकिया	35		
स्लोवेनिया	21		
सॉलोमन द्वीप समूह	142		
दक्षिण अफ़्रीका	123	↑	1
स्पेन	23		
श्रीलंका	97	↑	1
सूडान	169		
सूरीनाम	104		
स्वाज़ीलैंड	140	↓	–2
स्वीडन	10		
स्विट्ज़रलैंड	11		
सीरियाई अरब गणराज्य	119	↓	–1
ताजिकिस्तान	127		
तंज़ानिआ संयुक्त गणराज्य	152	↑	1
थाईलैंड	103		
टिमोर लेस्ट	147		
टोगो	162		
टोन्गा	90		
ट्रिनिडाड एवं टोबैगो	62	↑	1
ट्यूनिशिया	94	↓	–1
टर्की	92	↑	3
तुर्कमेनिस्तान	102		
युगान्डा	161		
यूक्रेन	76	↑	3
संयुक्त अरब अमीरात	30		
यूनाइटेड किंगडम	28		
यूनाइटेड स्टेट्स	4		
उरुग्वे	48		
उज़्बेकिस्तान	115		
वनुआतू	125	↓	–2
वेनेज़ुएला, बोलीवियाई गणराज्य	73		
वियतनाम	128		
यमन	154		
ज़ाम्बिया	164	↑	1
ज़िम्बाब्वे	173		

नोटः तीर की दिशा 2010 से 2011 के बीच श्रेणी में देश के ऊपर अथवा नीचे खिसकने का सूचक है, सुसंगत आँकड़ों और कार्यविधियों के आधार पर, देश के आगे किसी सूचक तीर का अभाव उसकी यथास्थिति का द्योतक है।

मानव विकास सूचकांक

एच.डी.आई. श्रेणी	मानव विकास सूचकांक (एच.डी.आई.) मान	असमानता समायोजित एच.डी.आई मान	असमानता समायोजित एच.डी.आई श्रेणी	लैंगिक असमानता सूचकांक मान	लैंगिक असमानता सूचकांक श्रेणी	बहु-आयामी निर्धनता सूचकांक
अति उच्च मानव विकास						
1 नार्वे	0.943	0.890	1	0.075	6	..
2 आस्ट्रेलिया	0.929	0.856	2	0.136	18	..
3 नीदरलैण्ड	0.910	0.846	4	0.052	2	..
4 यूनाइटेड स्टेट्स	0.910	0.771	23	0.299	47	..
5 न्यूज़ीलैण्ड	0.908	..	..	0.195	32	..
6 कनाडा	0.908	0.829	12	0.140	20	..
7 आयरलैण्ड	0.908	0.843	6	0.203	33	..
8 लिक्टन्सटाइन	0.905	..	..	..	..	..
9 जर्मनी	0.905	0.842	7	0.085	7	..
10 स्वीडन	0.904	0.851	3	0.049	1	..
11 स्विट्ज़रलैण्ड	0.903	0.840	9	0.067	4	..
12 जापान	0.901	..	..	0.123	14	..
13 हांग-कांग, चीन (एस.ए.आर.)	0.898	..	..	..	..	..
14 आइसलैण्ड	0.898	0.845	5	0.099	9	..
15 कोरिया गणराज्य	0.897	0.749	28	0.111	11	..
16 डेनमार्क	0.895	0.842	8	0.060	3	..
17 इसाइल	0.888	0.779	21	0.145	22	..
18 बेल्जियम	0.886	0.819	15	0.114	12	..
19 ऑस्ट्रिया	0.885	0.820	14	0.131	16	..
20 फ्रांस	0.884	0.804	16	0.106	10	..
21 स्लोवेनिया	0.884	0.837	10	0.175	28	0.000
22 फ़िनलैण्ड	0.882	0.833	11	0.075	5	..
23 स्पेन	0.878	0.799	17	0.117	13	..
24 इटली	0.874	0.779	22	0.124	15	..
25 लक्ज़मबर्ग	0.867	0.799	18	0.169	26	..
26 सिंगापुर	0.866	..	..	0.086	8	..
27 चेक गणराज्य	0.865	0.821	13	0.136	17	0.010
28 यूनाइटेड किंगडम	0.863	0.791	19	0.209	34	..
29 ग्रीस	0.861	0.756	26	0.162	24	..
30 संयुक्त अरब अमीरात	0.846	..	..	0.234	38	0.002
31 साइप्रस	0.840	0.755	27	0.141	21	..
32 एन्डोरा	0.838	..	..	..	..	..
33 ब्रूनेई दारुसलम	0.838	..	..	..	..	..
34 एस्टोनिया	0.835	0.769	24	0.194	30	0.026
35 स्लोवाकिया	0.834	0.787	20	0.194	31	0.000
36 माल्टा	0.832	..	..	0.272	42	..
37 कतर	0.831	..	..	0.549	111	..
38 हंगरी	0.816	0.759	25	0.237	39	0.016
39 पोलैण्ड	0.813	0.734	29	0.164	25	..
40 लिथुआनिया	0.810	0.730	30	0.192	29	..
41 पुर्तगाल	0.809	0.726	31	0.140	19	..
42 बहरीन	0.806	..	..	0.288	44	..
43 लात्विया	0.805	0.717	33	0.216	36	0.006
44 चिली	0.805	0.652	44	0.374	68	..
45 अर्जेन्टीना	0.797	0.641	47	0.372	67	0.011
46 क्रोएशिया	0.796	0.675	38	0.170	27	0.016
47 बारबाडोस	0.793	..	..	0.364	65	..
उच्च मानव विकास						
48 उरुग्वे	0.783	0.654	43	0.352	62	0.006
49 पलाऊ	0.782	..	..	..	..	..
50 रोमानिया	0.781	0.683	36	0.333	55	..
51 क्यूबा	0.776	..	..	0.337	58	..
52 सेशल्स	0.773	..	..	..	..	..
53 बहामास	0.771	0.658	41	0.332	54	..
54 मॉन्टीनेग्रो	0.771	0.718	32	..	..	0.006
55 बुल्गारिया	0.771	0.683	37	0.245	40	..
56 सऊदी अरब	0.770	..	..	0.646	135	..
57 मैक्सिको	0.770	0.589	56	0.448	79	0.015
58 पनामा	0.768	0.579	57	0.492	95	..

एच.डी.आई. श्रेणी	मानव विकास सूचकांक (एच.डी.आई.) मान	असमानता समायोजित एच.डी.आई मान	असमानता समायोजित एच.डी.आई श्रेणी	लैंगिक असमानता सूचकांक मान	लैंगिक असमानता सूचकांक श्रेणी	बहु-आयामी निर्धनता सूचकांक
59 सर्बिया	0.766	0.694	34	..	..	0.003
60 एन्टिगुआ एवं बरबूडा	0.764	..	..	..	..	..
61 मलेशिया	0.761	..	..	0.286	43	..
62 त्रिनिडाड एवं टुबैगो	0.760	0.644	46	0.331	53	0.020
63 कुवैत	0.760	..	..	0.229	37	..
64 लीबिया	0.760	..	..	0.314	51	..
65 बेलारूस	0.756	0.693	35	..	..	0.000
66 रशियन फेडरेशन	0.755	0.670	39	0.338	59	0.005
67 ग्रेनाडा	0.748	..	..	..	..	..
68 कज़ाकिस्तान	0.745	0.656	42	0.334	56	0.002
69 कोस्टारिका	0.744	0.591	55	0.361	64	..
70 अल्बानिया	0.739	0.637	49	0.271	41	0.005
71 लेबनान	0.739	0.570	59	0.440	76	..
72 सेन्ट किट्स एवं नेविस	0.735	..	..	..	..	..
73 वेनेज़ुएला	0.735	0.540	67	0.447	78	..
74 बोस्निया एवं हर्ज़ेगोविना	0.733	0.649	45	..	..	0.003
75 जॉर्जिया	0.733	0.630	51	0.418	73	0.003
76 उक्रेन	0.729	0.662	40	0.335	57	0.008
77 मॉरिशस	0.728	0.631	50	0.353	63	..
78 मेसाडोनिया, पूर्ववर्ती यूगोस्लाव गणराज्य	0.728	0.609	54	0.151	23	0.008
79 जमैका	0.727	0.610	53	0.450	81	..
80 पेरू	0.725	0.557	63	0.415	72	0.086
81 डोमिनिका	0.724	..	..	..	..	..
82 सेन्ट लूसिया	0.723	..	..	..	..	..
83 इक्वाडोर	0.720	0.535	69	0.469	85	0.009
84 ब्राज़ील	0.718	0.519	73	0.449	80	0.011
85 सेन्ट विन्सेन्ट एवं ग्रेनाडाइन्स	0.717	..	..	..	..	..
86 आर्मेनिया	0.716	0.639	48	0.343	60	0.004
87 कोलम्बिया	0.710	0.479	86	0.482	91	0.022
88 ईरान, इस्लामिक गणराज्य	0.707	..	..	0.485	92	..
89 ओमान	0.705	..	..	0.309	49	..
90 टोन्गा	0.704	..	..	..	..	..
91 अज़रबैजान	0.700	0.620	52	0.314	50	0.021
92 टर्की	0.699	0.542	66	0.443	77	0.028
93 बेलीज़	0.699	..	..	0.493	97	0.024
94 ट्यूनिशिया	0.698	0.523	72	0.293	45	0.010
मध्यम मानव विकास						
95 जॉर्डन	0.698	0.565	61	0.456	83	0.008
96 अल्जीरिया	0.698	..	..	0.412	71	..
97 श्रीलंका	0.691	0.579	58	0.419	74	0.021
98 डोमिनिकन गणराज्य	0.689	0.510	77	0.480	90	0.018
99 समोआ	0.688	..	..	..	..	..
100 फ़िजी	0.688	..	..	..	..	..
101 चीन	0.687	0.534	70	0.209	35	0.056
102 तुर्कमेनिस्तान	0.686	..	..	..	..	..
103 थाईलैण्ड	0.682	0.537	68	0.382	69	0.006
104 सूरीनाम	0.680	0.518	74	..	..	0.039
105 अल सल्वाडोर	0.674	0.495	83	0.487	93	..
106 गैबन	0.674	0.543	65	0.509	103	0.161
107 पराग्वे	0.665	0.505	78	0.476	87	0.064
108 प्लूरीनेशनल स्टेट ऑफ़ बोलीविया	0.663	0.437	87	0.476	88	0.089
109 माल्दीव	0.661	0.495	82	0.320	52	0.018
110 मंगोलिया	0.653	0.563	62	0.410	70	0.065
111 मॉल्डोवा गणराज्य	0.649	0.569	60	0.298	46	0.007
112 फ़िलीपीन्स	0.644	0.516	75	0.427	75	0.064
113 मिस्र	0.644	0.489	85	..	..	0.024
114 फ़लस्तीनी अधिकृत क्षेत्र	0.641	..	..	..	..	0.005
115 उज़बेकिस्तान	0.641	0.544	64	..	..	0.008
116 फेडरेटेड स्टेट ऑफ़ माइक्रोनेशिया	0.636	0.390	94	..	..	..
117 गयाना	0.633	0.492	84	0.511	106	0.053
118 बोत्स्वाना	0.633	..	..	0.507	102	..
119 सीरियाई अरब गणराज्य	0.632	0.503	80	0.474	86	0.021
120 नामीबिया	0.625	0.353	99	0.466	84	0.187

एच.डी.आई. श्रेणी	मानव विकास सूचकांक (एच.डी.आई.) मान	असमानता समायोजित एच.डी.आई मान	असमानता समायोजित एच.डी.आई श्रेणी	लैंगिक असमानता सूचकांक मान	लैंगिक असमानता सूचकांक श्रेणी	बहु-आयामी निर्धनता सूचकांक
121 हॉन्ड्यूरास	0.625	0.427	89	0.511	105	0.159
122 किरिबाती	0.624	..	..	..	..	..
123 दक्षिण अफ़्रीका	0.619	..	..	0.490	94	0.057
124 इण्डोनेशिया	0.617	0.504	79	0.505	100	0.095
125 वनुआतू	0.617	..	..	..	..	0.129
126 किर्गिस्तान	0.615	0.526	71	0.370	66	0.019
127 तजाँकिस्तान	0.607	0.500	81	0.347	61	0.068
128 वियतनाम	0.593	0.510	76	0.305	48	0.084
129 निकारागुआ	0.589	0.427	88	0.506	101	0.128
130 मोरक्को	0.582	0.409	90	0.510	104	0.048
131 ग्वाटेमाला	0.574	0.393	92	0.542	109	0.127
132 इराक	0.573	..	..	0.579	117	0.059
133 केप वर्दे	0.568	..	..	..	..	..
134 भारत	0.547	0.392	93	0.617	129	0.283
135 घाना	0.541	0.367	96	0.598	122	0.144
136 इक्वाटोरियल गिनी	0.537	..	..	..	..	..
137 कॉन्गो	0.533	0.367	97	0.628	132	0.208
138 लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक	0.524	0.405	91	0.513	107	0.267
139 कम्बोडिया	0.523	0.380	95	0.500	99	0.251
140 स्वाज़ीलैण्ड	0.522	0.338	103	0.546	110	0.184
141 भूटान	0.522	..	..	0.495	98	0.119
निम्न मानव विकास						
142 सॉलोमन द्वीप समूह	0.510	..	..	..	..	..
143 केन्या	0.509	0.338	102	0.627	130	0.229
144 साओ टोमे एवं प्रिन्साइप	0.509	0.348	100	..	..	0.154
145 पाकिस्तान	0.504	0.346	101	0.573	115	0.264
146 बांग्लादेश	0.500	0.363	98	0.550	112	0.292
147 टिमोर-लेस्ट	0.495	0.332	105	..	..	0.360
148 अंगोला	0.486	..	..	..	..	0.452
149 म्याँमार	0.483	..	..	0.492	96	0.154
150 कैमरून	0.482	0.321	107	0.639	134	0.287
151 मैडागास्कर	0.480	0.332	104	..	..	0.357
152 तन्ज़ानिया संयुक्त गणराज्य	0.466	0.332	106	0.590	119	0.367
153 पापुआ न्यू गिनी	0.466	..	..	0.674	140	..
154 यमन	0.462	0.312	108	0.769	146	0.283
155 सेनेगल	0.459	0.304	109	0.566	114	0.384
156 नाइजीरिया	0.459	0.278	116	..	..	0.310
157 नेपाल	0.458	0.301	111	0.558	113	0.350
158 हैती	0.454	0.271	121	0.599	123	0.299
159 मॉरिटानिया	0.453	0.298	112	0.605	126	0.352
160 लेसोथो	0.450	0.288	115	0.532	108	0.156
161 युगान्डा	0.446	0.296	113	0.577	116	0.367
162 टोगो	0.435	0.289	114	0.602	124	0.284
163 कॉमोरोस	0.433	..	..	..	..	0.408
164 ज़ाम्बिया	0.430	0.303	110	0.627	131	0.328
165 जिबूती	0.430	0.275	118	..	..	0.139
166 रवाण्डा	0.429	0.276	117	0.453	82	0.426
167 बेनिन	0.427	0.274	119	0.634	133	0.412
168 गैम्बिया	0.420	..	..	0.610	127	0.324
169 सूडान	0.408	..	..	0.611	128	..
170 आइवरी कोस्ट	0.400	0.246	124	0.655	136	0.353
171 मलावी	0.400	0.272	120	0.594	120	0.381
172 अफ़ग़ानिस्तान	0.398	..	..	0.707	141	..
173 ज़िम्बाब्वे	0.376	0.268	122	0.583	118	0.180
174 इथियोपिया	0.363	0.247	123	..	..	0.562
175 माली	0.359	..	..	0.712	143	0.558
176 गिनी-बिसाऊ	0.353	0.207	129	..	..	..
177 एरिट्रिया	0.349	..	..	..	..	..
178 गिनी	0.344	0.211	128	..	..	0.506
179 सेन्ट्रल अफ़्रीकन रिपब्लिक	0.343	0.204	130	0.669	138	0.512
180 सिएरा लिओन	0.336	0.196	131	0.662	137	0.439
181 बुर्कीना फ़ासो	0.331	0.215	126	0.596	121	0.536
182 लाइबेरिया	0.329	0.213	127	0.671	139	0.485

मानव विकास सूचकांक

एच.डी.आई. श्रेणी	मानव विकास सूचकांक (एच.डी.आई.) मान	असमानता समायोजित एच.डी.आई मान	असमानता समायोजित एच.डी.आई श्रेणी	लैंगिक असमानता सूचकांक मान	लैंगिक असमानता सूचकांक श्रेणी	बहु-आयामी निर्धनता सूचकांक
183 चाड	0.328	0.196	132	0.735	145	0.344
184 मोज़ाम्बीक	0.322	0.229	125	0.602	125	0.512
185 बुरुण्डी	0.316	..	..	0.478	89	0.530
186 नाइजर	0.295	0.195	133	0.724	144	0.642
187 कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य	0.286	0.172	134	0.710	142	0.393
अन्य देश अथवा क्षेत्र						
कोरिया, लोकतांत्रिक जन गणराज्य	..	..	..	..	..	..
मार्शल द्वीप समूह	..	..	..	..	..	..
मोनाको	..	..	..	..	..	..
नाउरू	..	..	..	..	..	..
सैन मैरीनो	..	..	..	..	..	..
सोमालिया	..	..	..	..	..	0.514
तुवालू	..	..	..	..	..	..
मानव विकास सूचकांक समूह						
अति उच्च मानव विकास	0.889	0.787	—	0.224	—	—
उच्च मानव विकास	0.741	0.590	—	0.409	—	—
मध्यम मानव विकास	0.630	0.480	—	0.475	—	—
निम्न मानव विकास	0.456	0.304	—	0.606	—	—
क्षेत्र						
अरब देश	0.641	0.472	—	0.563	—	—
पूर्व एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र	0.671	0.528	—	..	—	—
यूरोप एवं मध्य एशिया	0.751	0.655	—	0.311	—	—
लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियाई क्षेत्र	0.731	0.540	—	0.445	—	—
दक्षिण एशिया	0.548	0.393	—	0.601	—	—
सब-सहारा अफ्रीका	0.463	0.303	—	0.610	—	—
न्यूनतम विकसित देश	0.439	0.296	—	0.594	—	—
छोटे द्वीपीय विकासशील देश	0.640	0.458	—	..	—	—
विश्व	0.682	0.525	—	0.492	—	—

नोट

सूचकांकों के आकलन में अलग-अलग वर्षों के आँकड़े प्रयुक्त हुए हैं—पूरी जानकारी एवं प्रस्तुत आँकड़ों पर सपूर्ण नोट्स व स्रोतों के लिए विस्तृत रिपोर्ट (ये विस्तार से http://hdr.undp.org पर उपलब्ध है) के सांयिकीय संलग्नक को देखें। देशों का वर्गीकरण एच.डी.आई. क्वार्टाइलों पर आधारित है—कोई देश अति उच्च मान वाले समूह में तब रखा गया है यदि उसका एच.डी.आई. सर्वोच्च क्वार्टाइल में है, उच्च समूह में यदि उसका एच.डी.आई. 51-75 पर्सेन्टाइल के बीच है, मध्यम समूह में यदि उसका एच.डी.आई. 26-50 पर्सेन्टाइल के बीच है और सबसे नीचे के क्वार्टाइल में एच.डी.आई. वाले देशों को निन समूह में रखा गया है। पिछली रिपोर्टों में तुलनात्मक के बजाय निरपेक्ष (absolute) थ्रेशोल्ड (thresholds) का उपयोग किया गया था।